

3 | **राजधानी**
दिल्ली में दौड़ेंगे देश में
सबसे ज्यादा ई-ऑटो

6 | **अभिमत**
राजनीति में
गरिमाहीन शब्दावली

10 | **विदेश**
रूसी हमले के खिलाफ सुरक्षा
अहम मोड़ पर है : राष्ट्रपति

11 | **राष्ट्रीय**
अब यूपी को चाहिए
सबसे ज्यादा बिजली

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 10 अंक 143
नई दिल्ली, शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण



नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com



लक्ष्मण महिला
क्रिकेट में निभा सकते
हैं बड़ी भूमिका
स्पोर्ट्स-12

अमेरिका-भारत ने की यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर चर्चा

● दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं एवं युद्धग्रस्त देश में बिगड़ती मानवीय स्थिति की भी समीक्षा की

● **रूसी विदेश मंत्री आज भारतीय नेतृत्व के साथ यूक्रेन समेत अन्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे**

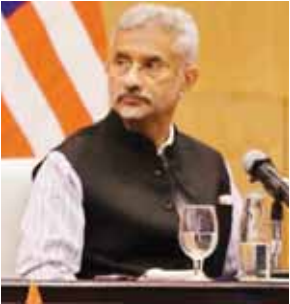
पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत और अमेरिका ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के प्रभाव पर चर्चा की है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, युद्धग्रस्त देश में बिगड़ती मानवीय स्थिति और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने की भी समीक्षा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन और उनके भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के बीच बुधवार देर रात टेलीफोन पर यूक्रेन समेत कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई।

जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अभी-अभी अमेरिकी विदेश मंत्री



ब्लिंकन के साथ उपयोगी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय सहयोग पर प्रगति की समीक्षा की। हिंद-प्रशांत, यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति और एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने के साझा प्रयासों, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाता है, सहित क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए बातचीत की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव के नई दिल्ली पहुंचने से कुछ घंटे पहले यह चर्चा हुई है। सर्गेई शुक्रवार को भारतीय नेतृत्व के साथ यूक्रेन समेत अन्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। बीते 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से यह किसी रूसी मंत्री की पहली भारत यात्रा है। रूसी मंत्री की अपने भारतीय समकक्ष के साथ



रुपये-रुबल व्यापार और रियायती कीमतों पर तेल की खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष भारत को एस-400 मिसाइल सहित हथियारों की आपूर्ति के बुधवार को मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भारत का दौरा पूरा किया, जिससे अलजीरिया से रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करने की अपील की गई। ब्लिंकन ने कहा कि उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों ने पहले रूस के सैन्य अभियानों के परिणामों को भुगता है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत और अमेरिका लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को भारत आए हैं। अपने आगमन के कुछ घंटे बाद, सिंह ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की। सिंह को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों को डिजाइन करने में एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता

यदि चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा नहीं करेगा: अमेरिका

नई दिल्ली। अमेरिका ने बृहस्पतिवार को कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में सक्रियता से गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही, यह भी कहा कि वह रूस से ऊर्जा एवं अन्य वस्तुओं सहित भारत के आयात में तीव्र वृद्धि देखना नहीं चाहेगा। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) दलीप सिंह ने मास्को एवं बीजिंग के बीच असमीमित साझेदारी का भी जिक्र किया और कहा कि किसी को भी ऐसा नहीं लाता है कि यदि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का उल्लंघन करता है तो रूस, भारत की रक्षा करने के लिए दौड़ा चला आएगा। सिंह ने कहा कि भारत का रूसी ऊर्जा का मौजूदा आयात अमेरिका के किसी प्रतिबंध (रूस के खिलाफ) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि अमेरिका ने रूस से ऊर्जा की आपूर्ति को छूट दे रखी है, लेकिन साथ ही वाशिंगटन अपने सहयोगियों को (शेष पेज 8)

भारत से संबंध मजबूत करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण

● **ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा**

भाषा। नई दिल्ली



ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत दौर पर आई ट्रस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के ठीक बाद यह टिप्पणी की। ट्रस ने कहा कि यूक्रेन संकट ने समान विचारधारा वाले देशों के एक साथ काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए यूक्रेन संकट के दूरगामी प्रभाव होंगे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने कहा, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक अधिक असुरक्षित दुनिया में रह रहे हैं, जो हम (क्लादिमीर) पुतिन के यूक्रेन पर भयावह आक्रमण के मामले में देख

रहे हैं। जयशंकर के साथ इंडिया-यूके स्ट्रेटिजिक प्यूसर्स फोरम को संबोधित करते हुए ट्रस ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। अपनी शुरुआती टिप्पणियों में ट्रस ने कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने रोडमैप-2030 के क्रियान्वयन में प्रगति के बारे में बात की जिसे पिछले साल मई में संबंधों की और व्यापक बनाने के लिए अपनाया गया था। वार्ता से पहले ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि लिज ट्रस जयशंकर से मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को (शेष पेज 8)

कहा कि जी-20 सहित आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।

नगालैंड, असम, मणिपुर में आफसपा का क्षेत्र घटा

● **केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा**

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि दशकों बाद एक अप्रैल से नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफसपा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाया जा रहा है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि उग्रवाद प्रभावित इन राज्यों से आफसपा को पूरी तरह से हटाया जा रहा है, बल्कि यह कानून तीन राज्यों के कुछ इलाकों में लागू रहेगा।

करीब तीन महीने पहले केंद्र ने नगालैंड से आफसपा को हटाने की संभावना को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। नगालैंड में पिछले साल दिसंबर में सेना ने गलत पहचान के मामले में 14 आम लोगों को मार दिया था। शाह ने ट्विस्ट पर कहा, एक अहम कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने नगालैंड,



असम और मणिपुर में दशकों बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत आने वाले अशांत इलाकों को घटाने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा में सुधार, निरंतर प्रयासों के कारण तेजी से हुए विकास, मोदी सरकार द्वारा उग्रवाद खत्म करने के लिए किए गए कई समझौतों और पूर्वोत्तर में स्थाई शांति के फलस्वरूप आफसपा के तहत आने वाले इलाकों को घटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से दशकों से उपेक्षा झेल रहा हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास का गवाह बन रहा है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों को इस अहम मौके पर बधाई देता हूँ। इन तीन पूर्वोत्तरी राज्यों में दशकों से आफसपा

लागू है जिसका मकसद क्षेत्र में उग्रवाद से निपटने के लिए तैनात सुरक्षा बलों की मदद करना है। आफसपा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है और अगर सुरक्षा बलों की गोली से किसी की मौत हो जाए तो भी यह उन्हें गिरफ्तारी और अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है। इस कानून के कथित कड़े प्रावधानों के कारण समूचे पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर से इसे पूरी तरह से हटाने के लिए प्रदर्शन होते रहे हैं।

मणिपुर की कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिता ने कानून को हटवाने के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल की। उन्होंने भी अगस्त 2016 को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। वर्ष 2015 में त्रिपुरा से और 2018 में मेघालय से आफसपा को पूरी तरह से हटा दिया था। समूचे असम में 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। स्थिति में अहम सुधार को देखते हुए एक अप्रैल से असम के 23 जिलों से आफसपा पूरी तरह हटाया जा रहा है जबकि एक जिले से यह आंशिक रूप से खत्म किया जा रहा है। इंफाल नगरपालिका के (शेष पेज 8)

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से लगेगा टोल

● **उत्तर प्रदेश के अन्य हाइवे व राजमार्गों पर टोल टैक्स में 10% का इजाफा**

● **दिल्ली से डायना तक फ्री, परंतु आगे हापुड़ या मेरठ जाने पर पूरे मार्ग की वसूली होगी**

● **दिल्ली से मेरठ तक 155 रुपए और दिल्ली से हापुड़ जा रहे हैं तो 140 रुपये लगेंगे**

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार आधी रात से टोल वसूली शुरू होगी यानी एक अप्रैल से दिल्ली से मेरठ के बीच मुफ्त सफर नहीं किया जा सकेगा। हालांकि टोल दिल्ली से डायना के बीच नहीं लगेगा, बल्कि डायना से आगे मेरठ या हापुड़ तक सफर करते हैं तो जेब ढीली करनी

पड़ेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स के रेटे शुक्रवार से बढ़ जाएंगे। एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा पर 10 प्रतिशत टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस बारे में एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय कैलेंडर के मुताबिक त्प साल एक अप्रैल से एनएचएआई की सभी हाईवे पर 10 प्रतिशत टोल की बढ़ोतरी की जाएगी और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मेरठ तक सफर करने वालों को 155 रुपए का टोल देना होगा। यदि दिल्ली से हापुड़ जा रहे हैं तो अब 140 रुपये का टोल देना होगा। पहले इस पर 130 रुपये टोल लगता था। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि हर साल एक अप्रैल को टोल की दरें संशोधित की जाती हैं। उसी क्रम में यह बढ़ोतरी हुई है। हापुड़ जिले में रजिस्टर्ड कमर्शल (शेष पेज 8)

इमरान और विपक्ष में समझौते के प्रयास जारी

● **संसद सत्र रविवार तक स्थागित, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं**

भाषा। लाहौर

दो प्रमुख सहयोगी दलों के पाला बदलने के बाद 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत खोने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त विपक्ष के बीच निचले सदन को भंग करने के लिए समझौते पर पिछले दरवाजे से प्रयास चल रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संघीय सरकार में उच्च पदस्थ सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार और संयुक्त विपक्ष के बीच पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही है।

सूत्र ने कहा, बातचीत एक बिंदु पर केंद्रित है- संयुक्त विपक्ष खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस लेगा और बदले में वह नेशनल असेंबली को त्प रिसे से चुनाव के

त्यागपत्र नहीं दूंगा: इमरान खान

भाषा। इस्लामाबाद



पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बहुमत खोने के बावजूद बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही, जोर देते हुए कहा कि वह रविवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करेंगे। राष्ट्र के नाम सीधे प्रसारण वाले एक संवोधन में खान (69) ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव

पर मतदान का चाहे जो कुछ नतीजा आए, वह और अधिक मजबूत होकर लौटेंगे। खान को, उन्हें प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने की विपक्ष की कोशिश को नाकाम करने के लिए 342 सदस्यीय संसद के निचले सदन में 172 वोट की जरूरत है। हालांकि, विपक्ष ने अपने पक्ष में 175 सांसदों का समर्थन हासिल होने का दावा किया और प्रधानमंत्री से फौरन इस्तीफा देने की मांग की है।

लिफ भंग करेंगे। उन्होंने कहा, अगर विपक्ष और सरकार के बीच समझौता हो जाता है तो प्रतिष्ठान में शीर्ष व्यक्ति गारंटर हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर यह समझौता हो जाता है, तो इस साल अगस्त में नए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि विपक्ष खान पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए गारंटर उसकी चिंताओं को शांत कर सकता है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी द्वारा बुधवार को सेना

प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री खान के बीच बैठक की पुष्टि के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। पाकिस्तान के अस्तित्व के 73 से अधिक वर्षों के आधे से अधिक समय तक देश पर शासन करने वाली शक्तिशाली सेना अब तक सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में काफी प्रभाव दिखाती रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (शेष पेज 8)

बाजार
सेंसेक्स 58,568 115
निफ्टी 17,464 33
सोना 51,542 117 /10g
चांदी 66,905 693 /kg

वित्तक न्यूज

हिजाब पहनी छात्राओं को परीक्षा की अनुमति देने पर सात शिक्षक निलंबित
बेगलुका राज्य के गडवा जिले में कथित तौर पर हिजाब पहने लड़कियों को 10वीं वी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले सात शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी। निलंबित शिक्षक सीएस पाटिल स्कूल ने परीक्षा रीतिरिक्त की। उन्होंने बताया कि दो अन्य शिक्षकों को केंद्र प्रीक्षक थे उन्हें भी निलंबित किया गया है। कार्यवाही इशालि वी गई क्योंकि यह कर्जाक उच्च न्यायालय के उस आदेश को खिलाफ था जिसने उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों वी याधिकाओं को छात्रिण कर दिया गया था। लड़कियों ने हिजाब या शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को गंवा करने वाले किसी भी कदम पर प्रतिबंध लगाने के सरकारों आदेश को चुनौती दी थी।

सोनिया ने मनरेगा बजट में कटौती का विषय उठाया

● **सरकार ने आरोपों का खंडन किया**

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में कटौती की गई है जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। सोनिया गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सरकार ने उनके आरोपों को तथ्यों से परे करार देते हुए कहा कि मनरेगा के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन हुआ है, जबकि पूर्व की संगम सरकार के समय न सिर्फ आवंटन कम था,



बल्कि भ्रष्टाचार भी होता था। सोनिया गांधी ने शुक्रवार के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा, मनरेगा का कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार-बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया, मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम (शेष पेज 8)

हवाई अड्डों से धड़ल्ले से हो रही वन्यजीवों की तस्करी

● **वन्य जीवों तक आसान पहुंच और कम यात्रा समय के कारण हवाई जहाज तस्करी की पहली पसंद**

● **अध्ययन में खुलासा एक दशक देश के 18 हवाई अड्डों पर तस्करी का सामान पकड़े जाने की 70,000 घटनाएं**

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

वन्यजीव तस्कर विमानन क्षेत्र की व्यापक पहुंच और यात्रा समय कम हो जाने का खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है



कि 2011 से 2020 तक दस वर्षों में 70,000 देशी-विदेशी जानवरों खासकर उनके शरीर के अंगों एवं ताल चंदन जैसे डेरिरेक्टिव में कहा गया है कि हवाई अड्डों से तस्करी करने का प्रयास किया गया। ट्रेफिक इंडिया द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट हाई फ्लाईंग थ्रू इनसाइट इन वाइल्डलाइफ ट्रेफिकिंग थ्रू इंडिया एयरपोर्ट्स में कहा गया है कि अवैध वन्यजीव उत्पादों की तस्करी में चेन्नई हवाई अड्डे का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। शोध के लेखक



डॉ. साकेत बडोला और आस्था गौतम ने कहा कि एक दशक की अवधि के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों से कम से कम 140 वन्यजीव जन्तु की घटनाएं सामने आई हैं। डॉ. साकेत ने कहा कि यह तो तस्करी किए जाने वाले सामान का बहुत छोटा सा हिस्सा है, वास्तविक तस्करी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश अवैध वन्यजीव व्यापार अनियंत्रित है, जिसका पता नहीं चल पाता। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के लिए हर तरह के

किया गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टार कछुआ आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्रायः सूची में दर्ज है। हालांकि, तस्कर स्पष्ट रूप से खतरे की स्थिति और परिशिष्ट -1 में अंतरराष्ट्रीय सीआईटीईएस नियमों की अवहेलना करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-2020 के बीच जब की गई देशी प्रजातियों में भारतीय स्टार कछुए की संख्या सबसे अधिक थी। जब कि एए प्रजातियों के समूहों में (भारतीय और विदेशी दोनों) प्रजातियों सहित), सीरपुस सबसे अधिक 46 प्रतिशत थे।

इसके बाद स्तनधारी 18 प्रतिशत, लकड़ी 13 प्रतिशत और समुद्री पर्यावरण से संबंधित प्रजातियां 10 प्रतिशत रहीं। यही नहीं, 12 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब की गई देशी प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या में भारतीय स्टार कछुआ, उसके बाद ब्लैक पॉन्ड टर्टल जियोक्लेमीस हैमिल्टन शामिल हैं, जबकि गैर-देशी (शेष पेज 8)

सीएम आवास पर तोड़फोड़ मामले में 8 गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज से की गई आरोपियों की पहचान, कुछ और लोग रडार पर



पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। आठों भाजपा युवा मोर्चे से जुड़े बताये जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक सभी आवास पर हुई तोड़फोड़ में शामिल थे। पुलिस ने मामले दर्ज करने के बाद सीसीटीवी खंगाले और चेहरे की पहचान की। धरपकड़ के लिए पुलिस की छह टीमों को गठित किया गया है। फिलहाल अभी कुछ और लोगों

सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण कोटा बहाल



राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात की। नड्डा से मुलाकात के बाद खट्टर ने कहा कि हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों में खिलाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। इसी क्रम में हरियाणा में ग्रुप सी की नियुक्तियों में 3 प्रतिशत आरक्षण कोटा की व्यवस्था को फिर बहाल कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रुप सी में 400 से 450 खिलाड़ियों को हर साल नौकरियां मिल सकेंगी। इस श्रेणी में

आबकारी नीति के विरोध में भाजपा ने सील किए 14 अवैध शराब के ठेके

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को 14 जिलों में 14 अवैध शराब के ठेकों को सील कर दिया। पटेल नगर में शुक्रवार को अवैध शराब के ठेके को सील करने के दौरान गुप्ता ने केजरीवाल का पुतला फूँका और कहा कि पुलिस का रिकॉर्ड यह कहता है कि शराब के ठेके खुलने से घरेलू हिंसा बढ़ी है जिसके जिम्मेवार केजरीवाल हैं।आदेश गुप्ता ने कहा कि महिलाएं, युवा, आरब्व्यूएफ, मार्केट एसोसिएशन एवं समाजिक संगठन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर कई अवैध शराब के ठेके को बंद करने का काम किया है। केजरीवाल जिस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली को शराब नगरी बनाने में लगे हुए हैं, उनकी मंशा भाजपा कभी कामयाब नहीं होने देगी। एक पर एक बोटल मुफ्त देने का सबसे बुरा असर फैक्ट्रियों में काम करने वाले दिहाड़ी

मजदूरों व फैक्ट्री मालिकों के ऊपर पड़ा है क्योंकि फैक्ट्री में काम करने की जगह मजदूर शराब के ठेकों के सामने लाइन में लगे रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपये की शराब बिकती है, लेकिन बावजूद उसके ड्राइ डेम कम कर शराब माफियाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में खुला शराब का ठेका ग्रामीणों के ढाई महीने के संघर्ष के बाद सील हो गया।



मजदूरों व फैक्ट्री मालिकों के ऊपर पड़ा है क्योंकि फैक्ट्री में काम करने की जगह मजदूर शराब के ठेकों के सामने लाइन में लगे रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपये की शराब बिकती है, लेकिन बावजूद उसके ड्राइ डेम कम कर शराब माफियाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में खुला शराब का ठेका ग्रामीणों के ढाई महीने के संघर्ष के बाद सील हो गया।

मजदूरों व फैक्ट्री मालिकों के ऊपर पड़ा है क्योंकि फैक्ट्री में काम करने की जगह मजदूर शराब के ठेकों के सामने लाइन में लगे रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपये की शराब बिकती है, लेकिन बावजूद उसके ड्राइ डेम कम कर शराब माफियाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में खुला शराब का ठेका ग्रामीणों के ढाई महीने के संघर्ष के बाद सील हो गया।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का पदभार शुक्रवार से संभालेंगे। कुमार 1 जनवरी 2012 से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत डॉ. मंगू सिंह से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। डॉ. सिंह का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त गया है।

डीएमआरसी में निदेशक (परिचालन) के पद पर कार्यरत कुमार को रेल आधारित शहरी परिवहन परियोजनाओं का तीन दशकों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है। भारतीय रेल यातायात सेवा के 1988 बैच के अधिकारी विकास कुमार ने सितंबर, 2004 में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है।

सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम



10 स्तर 2019-20 में 192 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था जो 2020-21 में से बढ़कर 193 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से 96 शहरों में 2019-2020 की अपेक्षा 2020-2021 में पीएम 10 की सांद्रता में कमी दर्ज की गई जबकि 31 शहरों में इसके स्तर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी लाने के लिए एक

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम



ई. ऑटो चलाती सुनीता चौधरी। फोटो: रंजन डिमरी

दिल्ली में दौड़ेंगे देश में सबसे ज्यादा ई. ऑटो

● मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो से दिखाई झंडी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक ऑटो आज से सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को आईपी डिपो से इलेक्ट्रिक ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कहा कि दिल्ली की सड़कों पर पर अब देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ेंगे। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली वाले एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इन ऑटो के शुरू होने से साढ़े तीन हजार से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। इसमें 500 महिलाएं भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद पहले साल में ही कुल खरीदे गए वाहनों में से 10 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन हैं। पिछले पांच साल में ईवी पॉलिसी के अंतर्गत 45 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। केजरीवाल ने

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई आगामी छह सितंबर को तय की गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनिय सांथी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केन्द्र, दिल्ली सरकार, लोक कार्य विभाग और दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की आगामी सुनवाई के लिए छह सितंबर को तारीख तय की है।

● वर्ष 2020-21 में से बढ़कर 193 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हुआ : केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री

राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि एनसीएसी के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों के लिए 423.21 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह राशि निगरानी नेटवर्क के विस्तार, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, हरित बफर क्षेत्रों, सड़कों की मरम्मतों से सफाई आदि जैसे उपायों के लिए मंजूर की गई है।

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

राजधानी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत तो की गई है लेकिन परिणाम सुखद नहीं रहे है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले 132 शहरों में से दिल्ली सहित 31 शहरों में 2020-21 के दौरान प्रदूषणकारी तत्व पीएम10 के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का पीएम

सभी मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी ईवी चार्जिंग की सुविधा

नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने बताया कि दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी का लक्ष्य है कि हर तीन किलोमीटर की परिधि में एक चार्जिंग प्वाइंट जरूर मिले। इसके लिए डिस्कॉम के साथ भी साझेदारी की है। आज की तारीख में सबसे सस्ता चार्जिंग प्वाइंट स्थापित कर सकते हैं, जो पूरे देश में मात्र दिल्ली में ही है। मात्र दो हजार देकर आप चार्जर लगा सकते हैं। आप अपने घर में भी ई-ऑटो को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, जितने भी दिल्ली मेट्रो रेल निगम के स्टेशन हैं, उन पर भी चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए बातचीत चल रही है। वहां भी हम इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का टेंडर किया था। वो भी सफल हो गया है और जल्द ही चालू हो जाएगा।

महिला व पुरुष ई-ऑटो चालकों को आरसी प्रदान किया। उन्होंने ई-ऑटो का मौका मुआयना किया। परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोट और विभाग के अधिकारियों ने उन्हें ई-ऑटो की विशेषताओं से अवगत कराया। सीएम एक महिला चालक के ऑटो में बैठकर कुछ दूर तक सवारी की और इन ऑटो की विशेषताओं और सुरक्षा पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सीएम ने चालक सुनीता चौधरी को मंच पर बुलाकर



शीला दीक्षित के तख्तीर पर पुष्पाजलि अर्पित करते चौधरी अनिल।

पूर्व सीएम शीला दीक्षित के जन्मदिन पर किया याद
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आज दिवंगत शीला दीक्षित को याद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने उनकी तख्तीर पर पुष्पाजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धाजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शीला के 15 वर्षों के शासन काल में दिल्ली का जो विकास हुए उससे राजधानी को विश्व एक अलग पहचान मिली और दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने पर शीला जी की सराहना विश्व स्तर पर हुई थी। उन्होंने कहा कि चहुमुखी विकास के लिए किए गए कार्यों और योगदान के लिए शीला जी को सदैव याद किया जाएगा। पुष्पाजलि अर्पित करने वालों में किरण वालिया, अनिल भारद्वाज, राजेश जैन, हरी शंकर गुप्ता, अमरीश गौतम, वीर सिंह धींगान, जिला अध्यक्ष मिर्जा जवाहद अली और जुबैर अहमद, हरी किशन जंदल और मौहम्मद उस्मान,एडवोकेट सुनील कुमार मुख्य रुप से शामिल थे।

राजधानी के स्कूलों को देखेंगे तमिलनाडु के सीएम

नई दिल्ली। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा कर सकते है। सूत्रों अनुसार दोनों नेता एक-दूसरे से मिलेंगे, जिसके बाद वे सरकारी स्कूलों के दौर पर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि स्टालिन दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में लाए गए बदलावों से काफी प्रभावित हैं। वह प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के इच्छुक हैं। साथ ही स्टालिन दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मोहल्ला क्लीनिक का भी दौरा कर सकते हैं। द्रमुक प्रमुख दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आर्थिक संकट से जुड़ रहे श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय मदद मुहैया करने की अनुमति देने की मांग की।

कोंडली इलाके में सीवर मौत मामले में केस दर्ज, तीन पकड़े

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में सीवेज शोधन संयंत्र में काम करने के दौरान छह फुट गहरे गड्ढे में गिरने से दो कर्मियों की मौत के बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में तीन लोगों को पकड़ा गया है और मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केपी तिवारी (प्लांट इंचार्ज), राजकुमार(फोमैन) तथा मोहम्मद हारून (शिफ्ट इंचार्ज) के रूप में हुई है। पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रियंका कश्यप ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध

और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत न्यू अशोक नगर थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान नितेश और यशदेव के तौर पर हुई है और दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद न्यू अशोक नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची। कश्यप ने कहा है कि टीम ने दोनों व्यक्तियों को संयंत्र के गड्ढे में गिरे हुए पाया। उन्हें दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति छह फुट गहरे गड्ढे में गिर गए थे।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में कही यह बात

राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए करें पत्रकारिता : कमल गुप्ता

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि भारत का इतिहास सदैव गौरवपूर्ण रहा है। भारत के इस प्राचीन इतिहास के पीछे अनेक कथाओं के साथ-साथ आंदोलन और संघर्ष की जो कहानी है, उसे मीडिया के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को बताना वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है। यह बात उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मीडिया संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र में कही। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को भी सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मीडिया जनता और शासन प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए पत्रकारों को सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्रहित में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता

दो दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया संवाद कार्यक्रम का समापन

करनी चाहिए। किसी भी देश का पतन तब होता है जब उस देश की मीडिया कमजोर होती है। मीडिया को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरें नहीं चलानी चाहिए, बल्कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर खबर दिखानी चाहिए क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी को अपना कायज करना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि शिक्षा-संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया है। इस दिशा में मीडिया एक सेतु का काम करती है। क्योंकि



गुरुग्राम विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया संवाद कार्यक्रम के समापन अवसर पर पत्रकार संजय कुमार मेहरा को सम्मानित करते शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता।

मीडिया हमें हमारे इतिहास के साथ-साथ देश का वर्तमान भी दिखाती है इसलिए, राष्ट्र की संरचना में मीडिया एक सेतु का काम करती है। क्योंकि

देश के कुछ मूलभूत सिद्धान्त और हमारा गौरवशाली इतिहास है।

इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने गुरुग्राम विवि में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया संवाद में शामिल होने वाले सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया को परिस्थिति के अनुसार ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाये। हमें नीतियों को इस तरह से फ्रेम करना चाहिए जिससे हमारे देश के युवाओं को बेहतर कल और उज्जवल भविष्य मिले।

हरियाणा सरकार के संयुक्त निदेशक, सूचना,जनसम्पर्क एवं भाषा, रणवीर सिंह सांगवान ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।

आईएमए ने डा. अर्चना शर्मा के निधन को बताया समाज के लिए क्षति

गुरुग्राम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुरुग्राम शाखा ने राजस्थान के दौसा में महिला चिकित्सक के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होती रही तो यह समाज को महंगा पड़ेगा। आए दिन चिकित्सकों के साथ पार्षद सुभाष सिंगला, अश्विनी शर्मा, हेमन्त, शीतल बागडी, भाजपा नेता अनिल यादव, पूर्व निगम पार्षद गजे सिंह कबलाना, भाजपा नेता अनिल यादव कन्हैवी व नीरज यादव सहित सभी दमकल केन्द्रों के अधिकारी उपस्थित थे।

गुरुग्राम आईएमए अध्यक्ष डॉ. एनपीएस वर्मा ने कहा कि ऐसी वारदात अक्सर हो रही हैं। इसकी वजह से अब अधिकतर डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते। जब भी मरीज को हालत गंभीर हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो रिश्तेदार और स्थानीय राजनीतिक लोग पैसे बनाने के चक्कर में डॉक्टर को तंग करते हैं। अस्पताल को तोड़फोड़ कर देते हैं। सचिव डॉ. सारिका वर्मा ने कहा कि राजस्थान के दौसा जिले में प्रसव के बाद महिला

संक्षिप्त समाचार

अचल यादव बने डीएलएफ द प्राइस आरडब्ल्यू के अध्यक्ष

गुरुग्राम। सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ द प्राइस आरडब्ल्यू के चुनाव गुरुवार को सर्वसम्मति से सम्पन्न हुए। इस चुनाव में अचल यादव को अध्यक्ष चुना गया। सोसायटी आरडब्ल्यू के चुनाव में अचल यादव को अध्यक्ष के अलावा सौरभ कुच्छल को उपाध्यक्ष, सुभाष वर्मा को महासचिव, केके वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रियंका और सेतिया को सदस्य बनाया गया है। अचल यादव ने कहा कि आरडब्ल्यू प्रतिनिधियों का कर्तव्य सोसायटी में रहने वाले लोगों के हित में, उनके लिए सुविधाओं के लिए काम करना होता है। इस काम में वे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सोसायटी के लोगों ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को कभी वे डिगने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के लोगों के हित के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। हर व्यक्ति को साथ लेकर वे चलेंगे। सोसायटी में लोगों के जो भी समस्याएं होंगी, उनका बिना देरी के निराकरण कराएंगे, ताकि लोगों को सहूलियत हो। उन्होंने यह भी कहा कि आरडब्ल्यू में जितने भी पदाधिकारी और सदस्य चुने गए हैं, सभी अपना कर्तव्य बेहतरी से निभाएंगे। लोग किसी भी जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि वह उनके दुख-तकलीफों में खड़ा मिले। उन्होंने फिर से विश्वास दिलाया कि पूरी आरडब्ल्यू जनहित में सदैव कार्यरत रहेगी।

36 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मेला लगा, आज से खुलेंगे प्ले स्कूल

सोहना। खंड के 36 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मेला उत्सव मनाया गया। मेला उत्सव में 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों से सर्वांगिक विकास से संबंध पुछताछ की गई। जिनका रिपोर्ट कार्ड तुरन्त अभिभावकों को दिया गया। शुक्रवार से आंगनवाड़ी से परिवर्तन करके बने 23 प्ले स्कूल को खोलने की तैयारियां शुरु हो गई है। वर्तमान समय में सोहना ब्लॉक के 222 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से मात्र 36 खुले हैं। जिनमें से 23 को प्ले स्कूल में परिवर्तन किया गया है। 23 प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले क़रीब आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर 300 बच्चों के आने की संभावना है। प्ले रेखा सोनी बच्चें से सर्वांगिक से संबंधित पुछताछ करते हुए।

के सभी 36 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मेला उत्सव मनाया। इस मेले उत्सव में बच्चों के साथ अभिभावकों को साथ बुलाया। प्ले स्कूलों में आने वाले बच्चों से सर्वांगीण विकास को लेकर पांच प्रकार की प्रक्रिया कराई गई। जिसमें सबसे पहला शारीरिक विकास, दूसरा संबोधित (दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का ज्ञान), भाषा का ज्ञान, रचनात्मक (बच्चों को सामग्री उपलब्ध करके उनसे कोई भी वस्तु बनवाना), गणित से संबंधित अंकों का ज्ञान तथा सामाजिक व भावनात्मक से संबंधित सवाल पूछे गए। सुपरवाइजर रेखा सोनी ने बताया कि मेला उत्सव में बच्चों के द्वारा सबालों के दिए गए जवाब और उसकी मानसिकता ज्ञान की जानकारी रिपोर्ट तुरन्त बनाई गई। तैयार की गई रिपोर्ट बच्चों के माता-पिता को तुरन्त दी गई। ताकि उन्हे अपने बच्चें की मानसिकता की जानकारी मिली। सीडीपीओ मंजू ने बताया कि खंड के सभी प्ले स्कूल प्रभारियों को एक अप्रैल से केन्द्रों को खोलने के आदेश जारी कर दिए है। स्कूलों को खोलने को लेकर गुरुवार को तैयारियों पूरी कर ली गई।

दूषित पानी की शिकायत मात्र पांच घंटे में की गई दूर



सोहना के वार्ड-18 में पेयजल आपूर्ति में आया दूषित पानी। जांच में जनस्वास्थ्य विभाग की टीम को लोक मिला घटलू पानी कनेक्शन।

सोहना। शहर के वार्ड-18 में पेयजल आपूर्ति में दूषित पानी आने से नागरिकों में भारी रोष। जिसकी शिकायत जनस्वास्थ्य विभाग को की गई। विभाग अधिकारी गुरुवार की शाम तक समस्या का समाधान करने का दावा कर रहे है। बुधवार की शाम से शहर के वार्ड-18 में पेयजल आपूर्ति में दूषित पानी आने से यहां के नागरिकों में हड़कौ मच गया। शहरवासियों ने बाजार से पीने के पानी की बोतलें खरीदकर अपने गले की प्यास को शांत किया। वार्ड-18 निवासी जयपाल का कहना है कि दूषित का उपयोग बर्तन धौने के लिए भी नहीं किया जा सकता। बदबूदार पानी को नागरिक बर्तनों में भरकर रखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। सरोज का कहना है कि साथ लगेते अन्य वार्डों से पीने के लिए पानी लेकर आए। पानी की कमी के कारण दो दिन से कपड़ों की धुलाई नहीं की है। जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार की सुबह ही वार्ड-18 में दूषित पानी की आपूर्ति की जांच में जुट गई। जेई खुशींद अहमद ने बताया कि घरेलू पानी का कनेक्शन लोक मिला है। यह कनेक्शन नाली के अंदर था। जिससे आगे जा रही प्यास की लाइन में नाली का गंदा पानी जा रहा था। एसडीओ ओमप्रकाश ने बताया कि गुरुवार की शाम तक दूषित पानी की आपूर्ति समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। गुरुवार की शाम को वार्ड में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी।

पुलिस ने दो बदमाशों को चोरी की बाइक समेत पकड़ा

सोहना। पुलिस ने शहर के पलबल मार्ग पर चोरी की बाइक व अवैध हथियार समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ सिटी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। सीआईए 40 गुरुग्राम पुलिस को बुधवार को शाम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि जिला पलवल का गांव छपरोला निवासी कृष्ण और टहरकी निवासी प्रेमचंद चोरी की बाइक पर सवार है। दोनों ही बदमाश पलवल मार्ग पर बना पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल डलवा रहे है। पुलिस टीम ने तुरन्त छापामारी करते हुए दोनों ही बदमाशों को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया। जिनकी तलाशी ली गई तो कृष्ण के पास से अवैध हथियार व प्रेमचंद के पास से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ बाइक चोरी करने तथा अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया है।

सीएम रहत कोष से उपचार को वित्तीय सहायता लेना आसान

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर ने कहा कि अंत्योदय के भाव के साथ हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में 22 गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने के साथ ही सभी आवेदनों को जिला स्तर पर उपायुक्त की संस्तुति पर मंजूरी देने का फैसला किया है। वे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों को नई प्रक्रिया के बारे में बताने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वी. उमाशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले निर्देशों के तहत पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाने के साथ ही समयबद्ध भी किया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सोधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा और वह चाहता है कि उपचार की राशि सोधे अस्पताल को मिले तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल्स भी साझा कर सकता है। श्री उमाशंकर ने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए आवेदक को इलाज से पूर्व अथवा इलाज के उपरांत जैसे दोनों विकल्प दिए गए हैं।

गुरुग्राम दमकल बेड़े में शामिल हुईं 8 नई गाड़ियां

जिला के सभी सातों फायर स्टेशन पर भेजी गईं ये गाड़ियां

मेयर ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

साइबर सिटी के दमकल बेड़े में सरकार की ओर से 8 नई दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। गुरुवार को मेयर मधु आजाद ने विधिवत पूजा-अर्चना करके नई गाड़ियों का स्वागत किया। हरी झंडी दिखाकर जिला के सातों फायर स्टेशनों की ओर रवाना किया।

मेयर मधु आजाद ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि गुरुग्राम जिला में प्रदेश सरकार द्वारा 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता भी थी। उन्होंने इसके लिए दमकल विभाग के उपनिदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा के प्रयासों की सराहना की। मेयर ने कहा कि इन 8 नई गाड़ियों के



गुरुग्राम के दमकल विभाग में शामिल नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करती मेयर मधु आजाद।

आने से गुरुग्राम का दमकल विभाग और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आग लगने जैसी घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के लिए प्रत्येक दमकल केन्द्र पर पर्याप्त वाहनों का होना अत्यंत आवश्यक है।

दमकल विभाग के उपनिदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई इन 8 गाड़ियों में 5 बड़ी गाड़ियां तथा 3 छोटी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें से पटीदी, उद्योग विहार, भीमनगर,

सेक्टर-29 व सेक्टर-37 में एक-एक बड़ी गाड़ी दी गई हैं। इसके अलावा सेक्टर-29, सोहना व मानेसर स्थित दमकल केन्द्रों में एक-एक छोटी गाड़ी दी गई है।

सेक्टर-29 में आयोजित कार्यक्रम में दमकल विभाग द्वारा दमकल वाहनों का प्रदर्शन भी किया गया। मेयर मधु आजाद ने निगम पार्षदों एवं अधिकारियों के साथ स्काई लिफ्ट में बैठकर अवलोकन किया। दमकल अधिकारियों से इसके

सोसायटी निर्माण संबंधी शिकायतों को लेकर गठित होगी स्ट्रक्चरल ऑडिट टीम

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जिला में बनी उंची इमारतों को वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों व आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ उपायुक्त ने बैठक कर उनके सुझाव आमंत्रित किए। बैठक में इमारतों के ढांचे संबंधी शिकायतों व समस्याओं के निवारण के साथ भविष्य में चिंतित्स पैराडिसो जैसी घटनाओं की पुनरावृति ना हो, इस विषय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेकर उठाए जाने वाले बिंदुओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों से इस बारे में अपने सुझाव 2 दिन में जिला प्रशासन को भेजने के लिए कहा है। प्राप्त सुझावों के उपरांत आगामी 10 दिनों के भीतर स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए टीम गठित कर दी जाएगी। बैठक में डीटीपी आरएस भाट् ने स्ट्रक्चरल



गुरुग्राम में निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों व आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ बैठक करते उपायुक्त निशांत कुमार यादव।

ऑडिट को लेकर उनके विभाग द्वारा अब किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

दो साल में 60 कॉलोनियों से मिली शिकायतें

उपायुक्त ने बताया कि जिला गुरुग्राम में पिछले दो वर्ष में इमारत के निर्माण में अनियमितता संबंधी 60 कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से शिकायत प्राप्त हुई हैं। उन्होने बताया कि इन शिकायतों के स्थाई समाधान तथा प्राप्त शिकायतों के

स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर व्यवस्था बनाते हुए कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उंची इमारतों में रहने वाले लोग उनके स्ट्रक्चर को लेकर सुरक्षित महसूस करें और वहां शांति से रह सकें, इसके लिए सभी को मिलकर व्यवस्था बनानी है। सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर अनुभवी विशेषज्ञों व स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर स्थाई समाधान खोजने

अहीर रेजिमेंट की मांग मजबूत करने को अन्य राज्यों में भी होंगे धरने

संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने लिया निर्णय

मोर्चा ने शुरु की आंदोलन को देशव्यापी बनाने की मुहिम

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर यहां खेड़कीदौला में चल रहे धरने को लोगों का समर्थन मिलना जारी है। गुरुवार को यहां दूसरा से ललित कुमार, भांगरोला से सुबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह, डाबोदा से पूर्व सरपंच दयाराम, जगदीश यादव, जीतू अहीरवाल, नखोड़ोला से दमन यादव, ससनपुर से अशोक यादव, कांटेरपुरी से राहुल यादव, जयनारायण यादव,



गुरुग्राम के खेड़कीदौला में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर एकता दिखाते समाज के लोग।

चंद्र से पूर्व सरपंच ओमप्रकाश, सुरेंद्र प्रधान, ऊंचा माजरा से केप्टन रामसिंह यादव तथा डॉ हरीश यादव

आदि धरने का समर्थन करने पहुंचे। इस अवसर पर धरना स्थल पर उपस्थित लोगों ने अहीर रेजिमेंट हक

है हमारा व जय यादव जय माधव के नारे लगाए। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की अगुवाई में जल्द ही पूरे देश

मेला : 20 साल में पहली बार ग्राहक का मुंह तक नहीं देखा

मेले में 1992 से आ रहे हैं, पहली बार 11 दिनों में नहीं हुई कोई बिक्री

कविता । फरीदाबाद

संत कबीर और नेशनल आवाड़ी गुजरात के कच्छ से सन 1992 से सूरजकुंड मेले में आ रहे दया भाई ने कहा कि इस बार 11 दिनों में एक भी रुपये की बिक्री नहीं हुई। इस बार संत कबीर आवाड़ी सभी हस्तशिल्पियों के लिए अलॉट स्टॉल दर्शकों की पहुंच से दूर हैं। वहीं 605 नम्बर स्टॉल पर बैठे सलाउद्दीन ने कहा कि वे उत्साह और उमंग लेकर आए थे। पिछले 11 दिनों से मनोबल टूट रहा है। इस बार का



606 स्टॉल पर बैठे दयाभाई।

मेला गलत समय पर लगा है। यदि मेला इस समय रखना था, तो पूरे मेले को ढकना चाहिए था।

35वें सूरजकुंड मेले में नेशनल और संत कबीर आवाड़ी हस्तशिल्पियों का इस बार आकर मनोबल टूट गया है। उनका कहना है कि फरवरी में लगने वाला मेला ही ठीक था, कुछ बिक्री तो होती



605 स्टॉल पर मौजूद सलाउद्दीन।

थी। लेकिन इस बार मार्च और अप्रैल की गर्मी के कारण बिक्री नहीं हुई है। वहीं उन्हें ऐसा स्थान दिया है, जहां दर्शक पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसे में पिछले 11 दिनों में उनकी बिक्री ही नहीं हुई।

जमीन आसमान का अंतर : संत कबीर और नेशनल आवाड़ी वनीकर दया भाई अला गुजरात के भूज

कच्छ को मेले में 606 नम्बर स्टॉल मिला है। उन्होंने बताया कि वह 1992 से सूरजकुंड मेले में आ रहे हैं। यहां पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पूछ ही नहीं हो रही। सभी संत कबीर आवाड़ी को एक तरफ फैक दिया है। इस बार मेले में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। वे वूलन आयटम

स्टॉल, शॉल, दुपट्टा, कार्टन की साड़ी लेकर आए हैं। लेकिन 11 दिनों में एक रुपये की भी बिक्री नहीं हुई।

टूट गया मनोबल : मेले में 605 नम्बर स्टॉल पर मौजूद सलाउद्दीन ने कहा कि वह पुस्तैनी हैंडलूम का काम बनारस में संभालते हैं। उनके सभी भाई भी यह काम करते हैं। केंद्र सरकार ने उनके भाई मगुआलम को 2017 में नेशनल आवार्ड दिया था। वहीं कमालुद्दीन को वर्ष 2018 में संत कबीर पुरस्कार मिला। वर्ष 2018 में मगुआलम को यूपी के सीएम ने विवरस पुरस्कार दिया था। वह मेले में उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन 11 दिन से बिक्री न होने से मलोबल टूट चुका है। संत कबीर पुरस्कार विजेताओं को यहां एक तरह से फैंक दिया है।

हेरोइन तस्क़र गिरफ्तार

फरीदाबाद। डीसीपी क्राइम नॉंद कादियान के द्वारा शहर में अपराधियों की धरपकड़ के दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम में अवैध नशा बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रणधीर और झाड़ी फरीदाबाद के एसजीएम नगर में रहता है। आरोपी दिल्ली के कर्ण से हेरोइन लेकर आता था।आरोपी को 29 मार्च को गिरफ्तार कर 7 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी कर्ण के घर दिल्ली से नशीले पदार्थ लाता है।ब्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी कर्ण के घर पर रेड की तो आरोपी मौके से फरार हो गया।घर से ब्राइम ब्रांच टीम में 36 ग्राम हेरोइन बरामद कर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली के थाना गुलाबी बाग में मुक दमा दर्ज कर दिया।

यातायात पुलिस ने नहर में कूदी महिला की बचाई जान

पायनियर समाचार सेवा । फरीदाबाद

सुबह सेक्टर-28 के नजदीक आगरा कैनाल में एक महिला ने छलांग लगा दी वहां पर तैनात यातायात पुलिस के जवानों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचन दी। यातायात पुलिस में तैनात उपनिरीक्षक विजय कुमार यादव होमगार्ड अभिषेक, विनोद तथा कुलदीप के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने देखा कि 28/29 वर्षीय महिला नहर में डूब रही है। यदि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो महिला की जान जा सकती है। पुलिस कर्मियों ने महिला की जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। वहां पर मौजूद अन्य लोगों की सहायता से महिला को सफल बाहर निकाल लिया। प्राथमिक उपचार देने के पश्चात महिला की हालत ठीक हो गई। पुलिस कर्मियों ने उसका नाम पता पूछा जिस पर महिला ने बताया कि वह भारत कॉलोनी को रहने वाली है। उसने बताया कि पति घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता है। इसलिए उनका



नदी में कूदी महिला को बाहर निकालते यातायात पुलिसकर्मों

कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस ने थाना खेड़ी पुल संपर्क किया। जहां से महिला को ले जाकर उसके लिए बयान करवाए जा रहे हैं। यह अक्सर देखा गया है कि ऐसी गंभीर दुर्घटना को लेकर आम आदमी जागरूक नहीं है। चाहे सड़क दुर्घटना का मामला हो या फिर बिजली के करंट का मामला हो या ऐसी वर्तमान जैसी परिस्थिति हो। यातायात पुलिस कर्मियों ने मानवता का फर्ज अदा किया है, जो अपनी ड्यूटी से हटकर समाज को एक आईना दिखा दिया है बल्कि जागरूक किया है।

सरकार का प्रदेश में 500 सरकारी कालेज खोलने का लक्ष्य : गुर्जर

सुपर 100 के बच्चों का आईआईटी व एमबीबीएस में दाखिला होना सरकार के साथ-साथ गरीब तबके की बड़ी कामयाबी

पायनियर समाचार सेवा । फरीदाबाद

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने को कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से सरकार ने 134 ए के नियमों में बदलाव करके नए शैक्षणिक सत्र से राइट टू एजुकेशन के तहत 25 फीसदी सीटें रिजर्व की हैं।

शिक्षा मंत्री गुरुवार को जिले के गांव बढौली निवासियों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बोल



गांव बढौली में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर।

रहे थे। इस स्कूल को अपग्रेड करके 10 + 2 करने पर ग्रामीणों की ओर से यह समारोह आयोजित किया गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में 22 सरकारी कॉलेज थे। अब हरियाणा में 138 सरकारी कॉलेज है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में 500 सरकारी कालेज खोले जाएं। विशेषकर महिलाओं की उच्चतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक कॉलेज खोले

जा रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि यह हरियाणा सरकार की पॉलिसी का ही सूपर 100 योजना के तहत पढ़ रहे 100 बच्चों में से 29 बच्चों का आईआईटी, 26 बच्चों का एमबीबीएस तथा 6 बच्चों का एम्स में दाखिला हुआ है। यह सभी बच्चे गरीब तबके से संबंध रखते हैं।

यह केवल सरकार ही नहीं गरीब समाज की भी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि

डॉक्टरों को बेगुनाही साबित करने को जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी ?

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बड़े ही दुख की बात है राजस्थान के जिला दौसा में लालसोट की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा जब अपनी एक मरीज को नहीं बचा पाई तो उसके विरुद्ध धारा 302 में मर्डर केस दर्ज कर दिया गया। जिससे वो इतनी ज्यादा आहत हुई कि उसने आत्महत्या कर ली।

डा सुरेश अरोड़ा ने बताया कि, 27 मार्च को डॉ अर्चना शर्मा ने अपने आनंद हॉस्पिटल में एक महिला का ऑपरेशन किया। उसके बाद जब उस पेशेंट को पीपीएच नामक कॉम्प्लिकेशन की वजह से व्तीडिंग हुई तो उन्होंने अपनी जी जान लगा कर बचाने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ हुए। मरीज के घरवाले पहले से ही उस डॉक्टर पर बहुत विश्वास करते थे और उनके यहां इलाज भी कराते रहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपना भाग्य समझते हुए अपने मरीज को बिना पोस्टमार्टम कराए अपनी मर्जी से घर ले गए, लेकिन घर पहुंचने पर कुछ स्वास्थ्य तत्वों ने उन्हें भड़काया और लालच दिलाने की कोशिश की। कहा कि आप शव को नर्सिंग होम के आगे ला कर रख

दीजिए। इस प्रकार दबाव डालने की कोशिश की गई। स्वार्थी और शरारती तत्वों के दबाव में पुलिस ने डॉ अर्चना शर्मा के खिलाफ दफा 302 में केस दर्ज कर दिया। इसके पश्चात डॉ अर्चना शर्मा इतनी ज्यादा दबाव में आ गई, कि उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखकर अपने आप को खत्म कर लिया। इस सुसाइड नोट में उन्होंने यह लिखा कि मैं इनोसेंट हूँ मेरे बच्चों को मेरे परिवार को कुछ ना कहा जाए और इनोसेंट डॉक्टर की रक्षा की जाए। यह एक कॉम्प्लिकेशन है जिससे कि मरीज की मौत हुई है। यह एक बहुत ही दुखद घटना है जिसका बाद से इस समय पूरे देश के डॉक्टर बहुत महसूस कर रहे हैं।

डा पुनीता हसीजा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले एक सरकारी अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है और 302 के तहत तो प्राथमिकी हो ही नहीं सकती क्योंकि 302 के तहत मर्डर केस की प्राथमिकी होती है। जो कि एक प्रोमिडीटेटेड मर्डर होता है।

रबर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल के लिए स्किल ट्रेनिंग

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

रबर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल (प्लास्टिक) सेक्टर, विशेष तौर पर एमएसएमई से जुड़ी सैकड़ों इकाइयों में कौशल विकास के लक्ष्य के साथ तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएनएसडीसी) ने रबर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट कार्डसिल (आरसीपीएसडीसी) से हाथ मिलाया है। आरसीपीएसडीसी इन तीनों क्षेत्रों के लिए सेक्टर स्किल कार्डसिल है और अब तक विभिन्न राज्यों में कौशल विकास अभियानों के साथ मिलकर देशभर में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का कौशल विकास कर चुका है।

आरसीपीएसडीसी तमिलनाडु में उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि तीनों सेक्टर में लोगों का गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास किया जाए। प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा। साथ ही उद्योगों को भी इससे जोड़ जाएगा। आरसीपीएसडीसी की सीओओ शिवानी नागपाल ने कहा,

'टीएनएसडीसी, जो राज्य में कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है, के साथ जुड़कर हमें खुशी हो रही है। तमिलनाडु देश में टायर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग भी अग्रणी है।इससे आरसीपीएसडीसी के पास यहां विशेषतौर पर रबर, टायर और प्लास्टिक के क्षेत्र में कौशल विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।'

शिवानी नागपाल ने आगे कहा, 'कारखानों में तेजी से टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल लोगों की जरूरत बढ़ी है। तमिलनाडु में कौशल विकास की माजबूत व्यवस्था है। आरसीपीएसडीसी से जुड़ने से इन तीन अहम सेक्टर में ट्रेनिंग की गुणवत्ता एवं मानकों को उन्नत करने में मदद मिलेगी, जिससे कौशल की कमी पूरा करे, प्रतिव्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने और कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।' समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत आरसीपीएसडीसी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूफ) के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करेगा, जिससे ट्रेनिंग के उच्च मानकों का पालन किया जा सके। प्रतिभागियों का मूल्यांकन एवं उन्हें



प्रमाणपत्र देने का कार्य नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स (एनओएस) के आधार पर किया जाएगा। ऑप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट में उद्योग जगत की सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में भी आरसीपीएसडीसी काम करेगा। प्रशिक्षकों को संबंधित कौशल, ज्ञान, दृल्ल एवं टेक्नोलॉजी में निपुण करने के लिए आरसीपीएसडीसी समय-समय पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) का आयोजन भी करेगा। इसके अतिरिक्त टीएनएसडीसी के अनुरूप आरसीपीएसडीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी करेगा। आरसीपीएसडीसी ने इससे पहले उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, एडिशनल स्किल्स एंकिजिशन प्रोग्राम, केरल, असम स्किल डेवलपमेंट मिशन और आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ गठजोड़ किया है।

अधिग्रहण से मुक्त जमीन की याचिका खारिज



फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के पांच गांवों की अधिग्रहण से मुक्त जमीन की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय सेक्टर-75 व 80 के पांच गांवों की किसानों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर चुका है। आज ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवदत्त वंशिष्ठ एडवोकेट ने

श्रेफ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवदत्त की अध्यक्षता में बैठक करते किसान।

एक बैठक कर उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी किसानों को दी। वंशिष्ठ ने कहा कि पांच गांवों की किसानों की जमीन को कांग्रेस की पिछली सरकार ने बगैर किसानों की मर्जी के मुआवजा 16 लाख में अधिग्रहित कर लिया था। इस अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने अपिल दायर की थी।

संक्षिप्त समाचार

फेस पेंटिंग में एमबीपी स्कूल की कीर्तिका ने मारी बाजी

फरीदाबाद। मेला परिसर स्थित छोटी चौपाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं का सिलसिला जारी है। गुरुवार को डिजाइनर गैलरी में फेस पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

फेस पेंटिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थी।

की गई, जिसमें जिलाभर के दस स्कूलों के 58 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें मार्टन बोपी स्कूल की कीर्तिका ने प्रथम, सेंट जानसन स्कूल की युक्ता और आर्य विद्या मंदिर स्कूल की प्राची ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार मार्टन बोपी स्कूल से अतुल कुमार और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनंगपुर की शिवानी तृतीय स्थान पर रहे। आर्य विद्या मंदिर की सरिता ने सात्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

फन कैप : कम्युनिकेटिव स्किल्स में दक्षता का पाठ पढ़ रही छात्राएं

फरीदाबाद।हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआईटी तीन फरीदाबाद में प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा की अध्यक्षता में कौशल विकास हेतु आयोजित किए जा रहे फन कैप में बालिकाएं कम्युनिकेटिव स्किल्स में दक्षता का अध्याय पढ़ कर निपुण हो रही हैं। इस शिविर में पचास छात्राएं प्रतिभागिता कर रही हैं। विद्यालय की जूनियर रेडक्रॉस और सेंट जॉन एंगुलेंस ब्रिगेड प्रभारी प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने कहा कि शिविर में भागीदारी कर रही छात्राएं बहुत ही उत्साहित हैं तथा कौशल विकास के लिए आयोजित किए जा रहे फन कैप में स्किल डिवेलप करने के साथ साथ विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञानोपार्जन भी कर रही हैं कम्युनिकेटिव स्किल्स एक्सपर्ट रिचा ने छात्राओं को अपनी वोकेबलरी एनरिच करने के मेथड्स पर चर्चा की और विशेष रूप से जिस भाषा में कम्युनिकेटिव स्किल डिवेलप करनी है उस भाषा में न्यूजपेपर, न्यूज चैनल के माध्यम से न्यूज सुनना और उसी भाषा की ख्याति प्राप्त पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कर्मी कांडसलर अनुक्रमा भाटी ने युवावस्था में हो रहे शारीरिक परिवर्तनों एवम बालिकाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत ज्ञानवर्धन किया। प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने अध्यापकों मोनिका, अंशुल, पूनम सहित सभी अध्यापकों, बालिकाओं और रिसोर्स पर्सन का भी बहुत बहुत आभार प्रकट किया।

परीक्षा परिणाम घोषित होने पर खुश हुए विद्यार्थी

फरीदाबाद। प्राइमरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित किया गया। पास होकर विद्यार्थी खुशी दिखे। अब इन विद्यार्थियों का नई कक्षाओं में एडमिशन किया जाएगा। जिले में 200 से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं और इनमें मॉडल संस्थाएँ स्कूल भी हैं, लेकिन दो साल बाद इन सभी विद्यार्थियों की ऑफ लाइन परीक्षाएँ हुईं और गुरुवार को इनका परिणाम घोषित किया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत सभी विद्यार्थियों को पास किया गया, लेकिन बेहतर अंक लेने पर विद्यार्थियों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर नाम बोल कर सम्मानित किया गया। गांव लकड़पुर के प्राइमरी स्कूता में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को बैग दिए गए। स्कूल की प्रिंसिपल किरण सिंह, मुख्य शिक्षक भगत सिंह, जेबीटी अस्थापक रेखा राज शर्मा, कविता देवी, ममता शर्मा, दीपा व वेदप्रकाश गौड़ मौजूद थे। ऐसे ही एतमादपुर, वजीरपुर समेत गांव भूपानी में भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिका पाठशाला भूपानी में मेधावी विद्यार्थियों को स्कूल प्राचार्य संदेश कुमार, मिडिल हेड अनीता चुग्रा व स्कूल ईंचार्ज अमित ने पुरस्कृत किया।

सेवानिवृत्त हुए दस पुलिस कर्मियों को दी विदाई

फरीदाबाद। विकास कुमार अरोड़ा पुलिस आयुक्त ने स्मृति चिन्ह देकर, नए जीवन की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य एवं सुखमय भविष्य की शुभकामनाओ के साथ दी विदाई पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पुलिस आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में फरीदाबाद पुलिस विभाग के सेवानिवृत्ति पाने वाले निरीक्षक करतार सिंह, जोगिन्द्र सिंह, सतपाल, सहायक उप निरीक्षक प्रदीप, अजीत, टेकन लाल, रमेश चन्द, सुरेन्द्र, मुख्य सिपाही राजपाल एवं ग्रुप-डी कर्मचारी कालू राम की सेवानिवृत्ति विदाई पार्टी आयोजित की गई किया गया। विकास कुमार अरोड़ा आईपीएस पुलिस आयुक्त द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी गई। जबान निरीक्षक करतार सिंह को अपने 37 साल 5 महिने की लम्बी सेवा पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त है। वही निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह पुलिस विभाग में 36 वर्ष 9 माह की लम्बी सेवा के उपरान्त पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त है। निरीक्षक सतपाल ने पुलिस विभाग में 39 वर्ष 10 महिने की लम्बी सेवा के उपरान्त पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त है। उप निरीक्षक प्रदीप ने पुलिस विभाग में 38 की लम्बी सेवा उपरान्त फरीदाबाद पुलिस में कार्य किया है। उप निरीक्षक अजीत सिंह ने पुलिस विभाग में 33 वर्ष 04 माह की लम्बी सेवा के उपरान्त पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त है। उप निरीक्षक टेकन लाल ने पुलिस विभाग में 33 वर्ष 04 माह की लम्बी सेवा के उपरान्त पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त है।

अस्पताल में चोरी करने वाला वाई बाॅय गिरफ्तार

फरीदाबाद। डीसीपी क्राइम नॉरेंद्र कादियान के द्वारा अपराधियों की धर-पकड़ के दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 की टीम ने अस्पताल ट्रिटेक काउंटर से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रमेश स्थाई रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के गांव भदानी का रहने वाला है और अस्थायी रूप से फरीदाबाद के ऊँचा गांव में रहता है। आरोपी मानवता हॉस्पिटल में चार-पांच महीने पहले नौकरी करता था। जो अब दोबारा 15 मार्च को मानवता हॉस्पिटल में वाई बाॅय की नौकरी पर लगा था। आरोपी ने 17 मार्च की रात को मानवता अस्पताल के कैश काउंटर से 200000 चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी 18 मार्च को हॉस्पिटल में ड्यूटी पर आया था। अस्पताल की कैश काउंटर के स्टाफ ने जब पैसें के बारे में पूछा तो आरोपी ने पैसे निकालने के बारे में कुबूल किया और मौके से फरार हो गया। मानवता अस्पताल के कैश काउंटर कर्मचारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले की तत्पंतीश क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 को मिली जिस पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को बख्शगढ़ के सेक्टर 65-64 चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अस्पताल में वाई बाॅय की नौकरी करता था। उसने कैश काउंटर पर इतने पैसे देखे तो उसकी नियत खराब हो गई जिसके कारण उसने चोरी की योजना बनाई। उसने 1 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे की तार हटा दी और मौका देख कर कैश काउंटर से 200000 रुपये चोरी कर लिए। आरोपी ने चोरी किए हुए पैसे एक औरत और एक आदमी को दिए गए। क्राइम ब्रांच टीम दोनों महिला और पुरुष आरोपियों की तलाश कर रही है जल्द ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा।

विधायक ने निगम संग वलाया सफाई अभियान

फरीदाबाद। विधायक नीरज शर्मा ने चौ. राणबीर सिंह हुड्डा लेजर वैली पार्क जिसको पूर्व मंत्री स्व: शिवचरण लाल शर्माजी ने अपने कार्यकाल में बनाया था। एनआईटी विधानसभा का यह सबसे बड़ा पार्क है। विधायक नीरज शर्मा ने पब्लिक को जागरूक करने के लिए विशेष सफाई अभियान की शुरुवात की, क्योंकि विधायक का कहना था की सफाई में आम जनता की भागीदारी को भी आवश्यकता है जब जनता जगहका होगी तो यह गंदगी खत्म हो जाएगी। विधायक नीरज शर्मा कहना है कि सफाई को लेकर एक जन अंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इस मौके पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नतिश पारवाल, हेडक्वार्टर इंचारज राजेन्द्र दाहिया, विधानसभा इंचारज बिशन तेवाविता, वार्ड-18 के इंचारज ओमप्रकाश शर्मा, वार्ड-10 के देशराज शर्मा, वार्ड-10 से पाणंद प्रतापशी पक्कंज शर्मा, चौ. पूरन सिंह, बोबी शर्मा एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

बंदियों के अधिकार

अनुशासन जरूरी

जेल में बंद कैदियों को अनुशासित करने की आवश्यकता है, पर यह मानवीय तरीके से होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महानिदेशक जेल से ऐसे तरीके खोजने को कहा जिनसे राजधानी की जेलों में हिंसा घटा कर अनुशासन बढ़ाया जा सके। अदालत को यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के समय आई जिसमें दावा किया गया था कि अराजक बंदियों को अनुशासित करने में अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाता है। अधिकारी ने अदालत को बताया कि जब दुर्दान्त अपराधियों की जगह बदली जाती है या जब उनसे बरामद प्रतिबंधित सामग्री के बारे में पूछताछ होती है तब हिंसा होती है। इनमें मोबाइल फोन, हथियार व यहां तक कि नशीले पदार्थ भी शामिल हैं। जेल निदेशक सुनवाई की अगली तारीख 20 मई को विस्तृत विवरण के साथ अदालत में पेश होंगे। राष्ट्रीय राजधानी तथा एक प्रकार से पूरे देश में जेल व्यवस्था में सुधार एक पवित्र रास्ता तलाशने की तरह है। दिल्ली में 16 जेलें हैं। उन सबमें बंदियों की संख्या बहुत अधिक तथा कर्मचारियों की संख्या कम है। ऐसे में रहने की स्थितियां, स्वच्छता मानक, स्वास्थ्यप्रद भोजन की उपलब्धता तथा व्यायाम पर सवाल उठते हैं। विधिक सहायता की कमी, विचारधीन या सजा काट चुके लोगों का अधिक समय तक बना रहना तथा बंदियों में अपराधी गैंगों का विकास समस्यायें और बढ़ाते हैं। ऐसे में काम के बोझ से लदे तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारी मानवीय व सभ्य



बनने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको विरले ही इस बात का प्रशिक्षण मिलता है कि जेलों को पुनर्वास का केन्द्र समझें। अधिकांश जेलरों की नजर में जेलें वह स्थान हैं जहां दोषियों को दंड देने के लिए भेजा जाता है। आप सरकार ने 2019 में उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने दिल्ली की जेलों में एक नया जेल मैनुअल लागू किया है। लेकिन काम का उल्लंघन न करे, सार्थक व्यावसायिक गतिविधियां उपलब्ध कराना, हस्तक्षेप करना तथा इस प्रकार बंदियों की रिहाई व उनको समाज में पुनः शामिल होने के लिए तैयार करना है।' ये काम तभी पूरे हो सकते हैं जब जेल के कर्मचारी शिक्षित, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, अच्छा वेतन पाने वाले तथा नियमित कार्यदिवस वाले हों। लेकिन विरले ही किसी जेल अधिकारी को अपने काम से संतुष्ट देखा जाता है। कथित रूप से उनमें से अनेक मिलीभगत करते हैं, जातीय राजनीति करते हैं, सामान छीनने तथा बंदियों में व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। हमें जेलों में जेल एवं बंदी प्रबंधन, अपराध विज्ञान, विधि, सामाजिक कार्य तथा पुनर्वास सहायता के नियमित व उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसा न होने के कारण ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ के अधिकारियों से जून, 2021 में कहा था, 'इन कारावाशों के कारण लोग हमारे देश में प्रत्यर्पण से बचते हैं। वे कहते हैं कि देखो भारतीय जेलों में क्या हो रहा है। लोगों की वहां पिटाई होती है। मुझे वहां न भेजें।'

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 2019 को एक रिपोर्ट में कहा था कि जेलों में भीड़ व हिंसा अथवा जेल अधिकारियों द्वारा अनुशासन लाने के लिए अवैध या अत्यधिक बल प्रयोग के कारण हिंसा भयानक रूप से बढ़ रही है। कैद तनहाई के अत्यधिक प्रयोग से विरले ही बंदी आज्ञाकारी बनते हैं। जेल कर्मचारियों द्वारा अत्याचार की जवाबदेही बहुत कम या एकदम गायब है। ऐसे में जेल मैनुअल भला किस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है? थार्नलैंड के इंस्टीट्यूट आफ जस्टिस की रिपोर्ट 'ग्लोबल प्रिज़न ट्रेंड्स 2020' में कहा गया था, 'जेल सेवा का काम सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना, जेल में दिन-प्रतिदिन का जीवन व्यवस्थित करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यवहार बंदियों की मानव गरिमा का उल्लंघन न करे, सार्थक व्यावसायिक गतिविधियां उपलब्ध कराना, हस्तक्षेप करना तथा इस प्रकार बंदियों की रिहाई व उनको समाज में पुनः शामिल होने के लिए तैयार करना है।' ये काम तभी पूरे हो सकते हैं जब जेल के कर्मचारी शिक्षित, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, अच्छा वेतन पाने वाले तथा नियमित कार्यदिवस वाले हों। लेकिन विरले ही किसी जेल अधिकारी को अपने काम से संतुष्ट देखा जाता है। कथित रूप से उनमें से अनेक मिलीभगत करते हैं, जातीय राजनीति करते हैं, सामान छीनने तथा बंदियों में व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। हमें जेलों में जेल एवं बंदी प्रबंधन, अपराध विज्ञान, विधि, सामाजिक कार्य तथा पुनर्वास सहायता के नियमित व उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसा न होने के कारण ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ के अधिकारियों से जून, 2021 में कहा था, 'इन कारावाशों के कारण लोग हमारे देश में प्रत्यर्पण से बचते हैं। वे कहते हैं कि देखो भारतीय जेलों में क्या हो रहा है। लोगों की वहां पिटाई होती है। मुझे वहां न भेजें।'

राजनीति में गरिमाहीन शब्दावली

राजनीति में जो लोग गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं वे देश तथा खासकर व्यवस्था का संचालन कैसे कर सकते हैं?



राजेंद्र प्रसाद गुमा
(लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं)

पिछले कुछ दशकों से जैसे निन्दाजनक शब्दों का प्रयोग भारतीय राजनीति में एक स्वीकृत मानक बन गया है। जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर अक्सर अशालीन टिप्पणियों की जाती हैं। महिलाओं को अक्सर तथाकथित 'सम्मानित' लोगों द्वारा अपमानजनक अभिव्यक्तियों का शिकार बनना पड़ता है जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। इन राजनेताओं को यह चिन्ता नहीं है क उनकी इन अनुपयुक्त टिप्पणियों का दीर्घकालीन रूप से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक बिहार का सवाल है, लालू यादव के राजनीति में आने और अशालीन भाषा के प्रयोग को वैध बनाने के बाद अन्य नेताओं ने भी बिना किसी जवाबदेही के अपमानजनक व असंसदीय भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह बीमारी अब संसद और ऐसी अभिव्यक्तियों को 'रिकार्ड' से हटाने का प्राविधान है, लेकिन चौबीसों घंटे व सातों दिन मीडिया कवरेज के युग में सुधारात्मक उपाय करने से पहले ही नुकसान हो जाता है।

24 अक्टूबर, 2021 को लालू यादव ने कांग्रेस के बिहार इन्चार्ज भक्त चरण दास को 'भक्वोनहर दास' कहा। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे। उदाहरणार्थ, उन्होंने रायबरेली में 21 फरवरी, 2017 को समाजवादी पार्टी की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शह के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों की थीं जिनको सभ्य समाज में दुहराया नहीं जा सकता है। 10 जनवरी, 2017 को उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सांसद साक्षी महाराज को गुंडा एक्ट के अंतर्गत जेल भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने उनको 'लफंदर' कहा था। उन्होंने गिरिराज सिंह को 'मंटल केस' कहा था। 18 दिसंबर, 2016 को



उन्होंने नोटबंदी की तुलना कांग्रेस काल के नसबंदी से की। अक्टूबर 2015 को दादरी घटना होने पर उन्होंने हिंदुओं को 'बीफ खाने वाला' बता दिया। जनवरी, 2017 में उन्होंने अनिल विज को भारत का 'नालायक बेटा' कहा। जनवरी, 2017 में उन्होंने विनय कटियार को 'टिकुली' व 'सिंदूर' लगाने की सलाह दी। 26 मार्च, 2017 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास की गंगा जल से धुलाई का आदेश दिया तो लालू ने उनको 'पिछड़ी जातियों का उत्पीड़क' तथा 'मुस्लिम-विरोधी' बता दिया। लालू यादव ने भाजपा सांसद हेमा मालिनी के बारे में भी विवादास्पद बयान दिए थे। 'बुड़बक' शब्द हमेशा उनकी ज़बान पर रहता है। लालू यादव ने पत्रकारों के प्रति भी यही दृष्टिकोण बनाए रखा। जून, 2017 में उन्होंने पत्रकारों से पृष्ठ सवालों के जवाब में कहा था, 'दे देंगे दो मुक्का, नाच कर गिर जाओगे'।

महिलायें भी इस देश में राजनेताओं की अनुपयुक्त भाषा का शिकार बनी हैं। 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता' वाले इस देश में महिलाओं के प्रति ऐसी

अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले राजनेता महिलाओं को सम्मान व अधिकार कैसे दे सकते हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने 2014 में युवाओं के खिलाफ बलात्कार के आरोपों पर कहा था, 'लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए उनको फांसी नहीं दी जा सकती है।'

जुलाई, 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंदसौर की महिला सांसद मौनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश की एक रैली में 'सौ टका टंच माल' कहा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का 'आइटम' कहा था। महिलाओं के प्रति ऐसी अनेक अश्लि टिप्पणियों से ये नेता महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। लालू यादव के अलावा उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, कमल नाथ, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, इमरान मसूद, व सोनिया गांधी भी ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं। मणि शंकर अय्यर ने 7 दिसंबर, 2017 को मोदी को 'नीच आदमी' कहा था। प्रियंका गांधी ने भी मोदी पर

'घटिया राजनीति' का आरोप लगाया था। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी को 'मौत का सौदागर' कहा था। ममता बनर्जी ने अमित शह और नरेन्द्र मोदी को दक्षिण दीनाजपुर में 22 अप्रैल, 2021 को हुई रैली में 'दिल्ली के गुंडे' कहा था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 18 जुलाई, 2018 को कहा था कि 'हिंदूवाद का तालिबानीकरण' हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'चपलों से मारने' की बात कही थी। उन्होंने राहुल गांधी को 'मूर्ख' नेता बताते हुए मणि शंकर अय्यर को 'जूतों से पीटने' की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल ध्वज का अपमान करते हुए कहा था कि 'यदि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35 हटाया गया और अनुच्छेद 370 हटाने का प्रयास हुआ तो जम्मू कश्मीर में भारतीय ध्वज का कोई निशान नहीं बचेगा।'

राजनेताओं के इन अस्वीकार्य व विवादास्पद भाषणों को स्वीकार कर उनके वारिस भी रोज ऐसी गालीगलौज वाली भाषा प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे विवादास्पद

बयान इन नेताओं की असलियत बताते हैं। कहा जाता है कि 'यदि आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसे बोलने दें।' किसी व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। जिनको भाषा की गरिमा का पालन नहीं करना है वे व्यवस्था कैसे चला सकते हैं? देश में ऐसे अनेक नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा भाषा की गरिमा बनाए रखी है और जनता ने उनका बहुत सम्मान किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था, पर वे कभी उत्तेजित नहीं दिखे। उन्होंने हमेशा सरलता और गंभीरता से अपनी बातें रखीं। इस कारण यह आंदोलन एक व्यापक व परिणामदायक आंदोलन बन गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा गरिमापूर्ण ढंग से विरोधियों का विरोध किया।

उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण शैली से सभी परिचित हैं। अपनी अलग शैली से वे विपक्ष को जवाब देते थे। राम मनोहर लोहिया, जार्ज फर्नान्डीज व लालकृष्ण आडवाणी भी ऐसे राजनेताओं में थे जिन्होंने अपने संयमित भाषणों से लोगों के दिलों पर राज किया और इसके बदले जनता ने उनको समुचित सम्मान दिया। राजनीतिक बहसों के लिए शब्दिक युद्ध की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनको सुनने तथा संयम के साथ जवाब देने की जरूरत होती है। कोई भी अच्छा नेता सामाजिक सद्भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करता है। ऐसे में जनता के लिए बेहतर है कि वह समाज के कल्याण हेतु काम के लिए नेता की स्वीकृति दे क्योंकि विवादास्पद टिप्पणियों से किसी खास वर्ग की आंख का तारा बनना उचित नहीं है।

अच्छे काम से मिलने वाली प्रशंसा स्थाई होती है तथा उसे युगों तक याद किया जाता है। राजनीति उकसावे वाले भाषणों पर जीवित नहीं रहेगी। तकनीकी की प्रगति से सूचना तक पहुंच ज्यादा आसान हो गई है। अब जनता जानती है कि कौन काम करने की आंख का तारा बनना उचित नहीं है। केवल बातें ही करेगा। जनता अपने नायक पहचानती है। इसलिए विवादास्पद लफ्फाजी के बजाय अच्छे कामों और व्यवहार की राजनीति समाज व देश के लिए लाभदायक है।

अन्नाद्रमुक की स्वर्ण जयंती



कुमार चेलपन्न
(लेखक दि पायनियर के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अपने एक काम में, विक्टर ह्यूगो ने कहा कि 40 जवानी की बुढ़ापा है जबकि 50 बुढ़ापे की जवानी है। अगर वह आज जीवित होते, तो ह्यूगो अन्नाद्रमुक में चल रही गतिविधियों से हैरान होते, जिसकी स्थापना 1972 में दिवंगत एमजी रामचंद्रन द्वारा की गई थी (वह 1977 में सत्ता में आए और 1987 में अपनी मृत्यु तक मुख्यमंत्री बने रहे) और जे जयललिता द्वारा मजबूत किया गया। पार्टी नेतृत्व, कैडर और कार्यकर्ता सनोभ्रंश से पीड़ित होना की संभावना है। 2016 में जयललिता के निधन के बाद से अन्नाद्रमुक एक अभूतपूर्व नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। एमजीआर के निधन के बाद, एक संथन प्रक्रिया ने देखा कि जयललिता, दक्षिण भारतीय फ़िल्म प्रशंसकों की एक दिल की धड़कन, अन्नाद्रमुक की निर्वािवाद नेता के रूप में उभरी और 5 दिसंबर 2016 को अंतिम सांस लेने तक नंबर वन बनी रहीं। प्रारंभ में, जयललिता को एमजीआर द्वारा निर्देशित किया गया था, हालांकि उन्होंने अपने तेज को साबित किया। इसी समय, तमिलनाडु सरकार के एक सहायक पीआरओ की

पत्नी वीके शशिकला ने उनके जीवन में प्रवेश किया। तब से, मैट्रिक पास शशिकला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो चेन्नई के पोएस गार्डन में अम्मा के विशाल बंगले वेद निलयम में जया की लिब-इन पार्टनर बनीं। हालांकि 1996 के विधानसभा चुनाव में जयललिता को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2001 और 2011 के चुनावों में एक चमत्कारी वापसी की, जिसमें द्रमुक को उखाड़ फेंका गया। 2014 का लोकसभा चुनाव केक पर आइसिंग था क्योंकि, द्रष्टव्य ने तमिलनाडु की 39 में से 37 सीटें जीती थीं। जया ने 2016 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी को जीत दिलाई लेकिन तब तक वह स्वास्थ्य और ऊर्जा खो चुकी थीं। उनके निधन से अन्नाद्रमुक के स्वर्ण युग का अंत हो गया।

ओ पनीरसेल्वम, जिन्होंने 6 दिसंबर की तड़के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, को शशिकला और उनके भतीजों के नेतृत्व वाली एक मंडली ने हटा दिया था, जिन्होंने 5 और 6 दिसंबर, 2016 की मध्यरात्रि में वेद निलयम पर नियंत्रण कर लिया था। शशिकला और उनके पूरे परिवार को अक्टूबर 2011 में जयललिता ने वेद निलयम से बाहर कर दिया था, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे कबीले के साथ कोई संपर्क न करें। लेकिन शशिकला को अप्रैल 2012 में पोएस गार्डन में यह घोषित करने के बाद फिर से भर्ती कराया गया कि वह केवल अपनी अक्का (जिस)



की सेवा करने में रुचि रखती हैं और राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगी। उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन, जिन्हें भी 2011 में वेद निलयम से हटा दिया गया था, जया के निधन के बाद बंगले में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। शशिकला ने उन्हें उप महासचिव नियुक्त किया, जो पार्टी में अब तक नहीं सुना गया था। दिसंबर 2016 तक, शशिकला को अन्नाद्रमुक के कार्यावाहक महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष शम्बी दुरई ने

महासचिव के रूप में शशिकला की पदोन्नति के लिए खुले तौर पर पैरवी की। पार्टी सुप्रीमो के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर, दुरई ने मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की मांग की। उसके बाद, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। फरवरी 2017 के पहले सप्ताह तक, अन्नाद्रमुक विधायक दल के एक विशेष सत्र ने सर्वसम्मति से शशिकला को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। शपथ ग्रहण समारोह 15 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के

आदेश के रूप में बिजली गिरी थी, जिसमें कर्नाटक विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें शशिकला, उनके भतीजे सुधाकरन और चचेरे भाई इलावरसी को आय से अधिक आय के मामले में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस दिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी थी, छिन्नम्मा एडप्पादी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री की नौकरी के सौंपने के बाद परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल जा रही थीं। पलानीस्वामी ने शैली में शुरुआत की लेकिन दिनाकरन ने शांट लगाना शुरू कर दिया। उनका मिशन (जया के) आरके नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना, पलानीस्वामी को गिराना और मुख्यमंत्री बनना था। शशिकला के जेल में होने के कारण, पलानीस्वामी ने भाजपा में अपने संपर्कों का इस्तेमाल पनीरसेल्वम को वश में करने के लिए किया, जिन्होंने अनिच्छा से उन्मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था।

सितंबर 2017 में एक सामान्य परिषद की बैठक ने शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से बाहर कर दिया। दिनाकरन ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कज्जम नामक एक संगठन लॉन्च किया, और अभी भी राज्य की राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में अन्नाद्रमुक को द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हराया था, लेकिन जीत का अंतर वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी को विपक्ष का नेता नहीं बनाने से नाराज हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन विघटन को

गति देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पलानीस्वामी के भरोसेमंद सहयोगियों (सभी गौंडर समुदाय से संबंधित) पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। पनीरसेल्वम और शशिकला, दोनों शक्तिशाली थेवर समुदाय से हैं, फरवरी 2017 में उनके खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा करने के बावजूद साथ मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशिकला में उस पार्टी की नेता सौंपने के बाद परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल जा रही थीं। पलानीस्वामी ने शैली में शुरुआत की लेकिन दिनाकरन ने शांट लगाना शुरू कर दिया। उनका मिशन (जया के) आरके नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना, पलानीस्वामी को गिराना और मुख्यमंत्री बनना था। शशिकला के जेल में होने के कारण, पलानीस्वामी ने भाजपा में अपने संपर्कों का इस्तेमाल पनीरसेल्वम को वश में करने के लिए किया, जिन्होंने अनिच्छा से उन्मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था।

सितंबर 2017 में एक सामान्य परिषद की बैठक ने शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से बाहर कर दिया। दिनाकरन ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कज्जम नामक एक संगठन लॉन्च किया, और अभी भी राज्य की राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में अन्नाद्रमुक को द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हराया था, लेकिन जीत का अंतर वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी को विपक्ष का नेता नहीं बनाने से नाराज हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन विघटन को

गति देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पलानीस्वामी के भरोसेमंद सहयोगियों (सभी गौंडर समुदाय से संबंधित) पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। पनीरसेल्वम और शशिकला, दोनों शक्तिशाली थेवर समुदाय से हैं, फरवरी 2017 में उनके खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा करने के बावजूद साथ मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशिकला में उस पार्टी की नेता सौंपने के बाद परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल जा रही थीं। पलानीस्वामी ने शैली में शुरुआत की लेकिन दिनाकरन ने शांट लगाना शुरू कर दिया। उनका मिशन (जया के) आरके नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना, पलानीस्वामी को गिराना और मुख्यमंत्री बनना था। शशिकला के जेल में होने के कारण, पलानीस्वामी ने भाजपा में अपने संपर्कों का इस्तेमाल पनीरसेल्वम को वश में करने के लिए किया, जिन्होंने अनिच्छा से उन्मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था।

सितंबर 2017 में एक सामान्य परिषद की बैठक ने शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से बाहर कर दिया। दिनाकरन ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कज्जम नामक एक संगठन लॉन्च किया, और अभी भी राज्य की राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में अन्नाद्रमुक को द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हराया था, लेकिन जीत का अंतर वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी को विपक्ष का नेता नहीं बनाने से नाराज हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन विघटन को

गति देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पलानीस्वामी के भरोसेमंद सहयोगियों (सभी गौंडर समुदाय से संबंधित) पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। पनीरसेल्वम और शशिकला, दोनों शक्तिशाली थेवर समुदाय से हैं, फरवरी 2017 में उनके खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा करने के बावजूद साथ मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशिकला में उस पार्टी की नेता सौंपने के बाद परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल जा रही थीं। पलानीस्वामी ने शैली में शुरुआत की लेकिन दिनाकरन ने शांट लगाना शुरू कर दिया। उनका मिशन (जया के) आरके नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना, पलानीस्वामी को गिराना और मुख्यमंत्री बनना था। शशिकला के जेल में होने के कारण, पलानीस्वामी ने भाजपा में अपने संपर्कों का इस्तेमाल पनीरसेल्वम को वश में करने के लिए किया, जिन्होंने अनिच्छा से उन्मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था।

सितंबर 2017 में एक सामान्य परिषद की बैठक ने शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से बाहर कर दिया। दिनाकरन ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कज्जम नामक एक संगठन लॉन्च किया, और अभी भी राज्य की राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में अन्नाद्रमुक को द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हराया था, लेकिन जीत का अंतर वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी को विपक्ष का नेता नहीं बनाने से नाराज हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन विघटन को

गति देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पलानीस्वामी के भरोसेमंद सहयोगियों (सभी गौंडर समुदाय से संबंधित) पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। पनीरसेल्वम और शशिकला, दोनों शक्तिशाली थेवर समुदाय से हैं, फरवरी 2017 में उनके खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा करने के बावजूद साथ मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशिकला में उस पार्टी की नेता सौंपने के बाद परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल जा रही थीं। पलानीस्वामी ने शैली में शुरुआत की लेकिन दिनाकरन ने शांट लगाना शुरू कर दिया। उनका मिशन (जया के) आरके नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना, पलानीस्वामी को गिराना और मुख्यमंत्री बनना था। शशिकला के जेल में होने के कारण, पलानीस्वामी ने भाजपा में अपने संपर्कों का इस्तेमाल पनीरसेल्वम को वश में करने के लिए किया, जिन्होंने अनिच्छा से उन्मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था।

आप की बात

त्वरित कदम उठाए सरकार

पश्चिम बंगाल का बीरभूम हिंसा का मामला वहां की स्थानीय पुलिस एवं सरकार की घोर लापरवाही का द्योतक है। लोगों के घरों में आग लगाकर उन्हें ज्वादा जला देना अराजकता की पराकाष्ठा है। विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव हुआ था। बेलगाम कार्यकर्ताओं पर वहां की सरकार लगाम लगाने में असमर्थ रही थी। बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ सीमावर्ती राज्य होने के कारण पश्चिम बंगाल में सत्ता के सूत्र एक सशक्त पार्टी के हाथ में होना चाहिए। पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार इसमें असफल सिद्ध हो रही

है। सुनियोजित तरीके से बहुसंख्यक लोगों को डरा धमका कर एवं उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर वहां की सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? लोकतांता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले की सीबीआई से जांच का आदेश देकर बिलकुल सही कदम उठाया है क्योंकि राज्य सरकार की एउआईटी जांच सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकती है। समय रहते केंद्र को हस्तक्षेप कर पश्चिम बंगाल में सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए एवं बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए।

- **ललित महालकरी**, इंदौर

पेपर आउट का खेल

अप्र में बुधस्पतिवार को देश की सबसे बड़ी माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा में इंटर अंग्रेजी का प्रश्नपत्र आउट हो गया। जिसके कारण 24 जिलों की परीक्षा शाम की पारी की निरस्त कर दी गई। जिलाविद्यालय निरीक्षक बलिया के साथ 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में मंडली ने हटा दिया था, जिन्होंने 5 और 6 दिसंबर, 2016 की मध्यरात्रि में वेद निलयम पर नियंत्रण कर लिया था। शशिकला और उनके पूरे परिवार को अक्टूबर 2011 में जयललिता ने वेद निलयम से बाहर कर दिया था, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे कबीले के साथ कोई संपर्क न करें। लेकिन शशिकला को अप्रैल 2012 में पोएस गार्डन में यह घोषित करने के बाद फिर से भर्ती कराया गया कि वह केवल अपनी अक्का (जिस)

- **कुलदीप मोहन त्रिवेदी**, जरावाग, उन्नाव

जल संरक्षण अनिवार्य

जल संकट गर्मी में विशेष चिंता का विषय होता है। बड़ी संख्या में लोग साफ-सुथरे पानी के लिए तरसते हैं। बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहने वाले पानी को इंदौर की तड़प प्रशंसनीय है। पानी बचाने और उसके दूसरी बार उपयोग के लिए जिस तरह सीवेज की तरफ ध्यान दिया गया है वह एक मॉडल हो सकता है। आने वाला समय पानी के नाम पर संकटदायी है ऐसे में इसे विविध तरीकों से सहेजे जाने की जरूरत है। इंदौर में पानी के क्षेत्र में भी

सफाई की उपलब्धि हासिल की है। जर जल पुरस्कार प्राप्त किया है। यह वाकई प्रशंसनीय है कि सीवेज में बहने वाला अनुपयोगी पानी आज उपचारित होकर दूसरी बार उपयोग में आ रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण और पुनर्भरण से जलस्तर भी सुधरा है। इस तरह के प्रयास अब शहरों से होकर गांव तक पहुंचना जरूरी है। प्रदेश भर में जल समाशोधन और उसके संचय के प्रयास होंगे तो तृप्त होती धरती से निरसिंदेह हमारी जरूरत पूरी होने की आशा की जा सकती है।

- **अमृतलाल मारू**, दसई, मप्र
पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।



यदि समाज में हिंसा की प्रवृति हो तो उसका विरोध किया जाना चाहिए।
- **नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री

भाजपा बार-बार इस देश के संघीय ढांचे पर हमले का प्रयास करती है।
- **ममता बनर्जी**
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा पर केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों में नया कुछ नहीं है।
- **सामिक भट्टाचार्य**
पश्चिम बंगाल भाजपा प्रवक्ता

जनप्रतिनिधि ही नहीं, अधिकारी भी गोद लें स्कूल: सीएम

चार अप्रैल को सीएम करेंगे स्कूल चलो अभियान की शुरुआत

● अगले पांच साल में एक करोड़ नए छात्र पंजीकरण का लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार दूसरे कार्यकाल में कामकाज संभालते ही प्राइमरी शिक्षा की तस्वीर बदलने में जुट गई है। आगामी 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्रवस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कम साक्षरता वाले जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 1.58 लाख प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ



बैठक में कहा कि 4 अप्रैल से श्रवस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी। इसके ध्यान में रखते हुए विभाग समय से सभी तैयारियां पूरी कर ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अध्यापक घर-घर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। स्कूल चलो अभियान के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। सभी विधायक एक-एक विद्यालय को गोद जरूर लें। इसके साथ ही

अधिकारी भी स्कूलों को गोद लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों की साक्षरता दर कम है उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाय। वहां के विद्यालयों में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रवस्ती से की जा रही है, वहां की साक्षरता दर प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक शिक्षा परिषद के सभी 1.58 लाख विद्यालयों को आच्छादित किया जाए। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाए। इसके लिए निजी संस्थाओं, स्कूल के पुराने विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जोड़ा जाए।



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी के समूहिक प्रयासों से कोरोना संक्रमण का खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर को संचालित रखे जाने के निर्देश दिये हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोग सम्पर्क कर सकें।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लोक भवन में टीम-9 की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को

के प्रत्येक नागरिक का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। 83 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क व्यक्तियों को कोरोना टीके की दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। 29 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज लगाने तथा 10 करोड़ 80 लाख से अधिक कोरोना सैम्पल की जांच करने वाला उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है। विगत दिवस तक 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 93 प्रतिशत से अधिक किशोरों ने कोरोना टीकाकरण की प्रथम डोज प्राप्त कर ली है। 124 लाख 19 हजार से अधिक पात्र व्यक्तियों ने प्री कोशन डोज भी प्राप्त कर ली है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 08 लाख 78 हजार से अधिक बच्चों ने कोरोना टीकाकरण की प्रथम डोज प्राप्त कर ली है।

चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ सीएम की बैठक

सौ दिनों में सरकार देगी दस हजार नौकरियां



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यह अपेक्षा की है कि सभी सेवा चयन बोर्ड 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए 10000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विगत 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पूर्व की भांति सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सभी चयन आयोगों बोर्डों को 100 दिवसीय 6 माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अध्यायन समय से भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। भर्ती प्रक्रिया को शुचित्वापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चुन एवं परीक्षा केन्द्रों के स्थानीय कच्चे माल का संस्करण के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला केन्द्र, परीक्षा केन्द्र न बने। परीक्षा केन्द्र निर्धारण में अभ्यर्थियों की

सहूलियतों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को सम्बन्धित संस्थाएं, शासन सम्बन्धित विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ संवाद एवं समन्वय बनाते हुए पूर्ण करें। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं तथा नियुक्ति प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। साक्षात्कार पैन्ल में सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर एवं संवेदनापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। बैठक के दौरान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोवेंट बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव गुरु अनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव सूचना मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री अलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नसीमुद्दीन ने दोबारा बसपा में जाने की अटकलों को किया खारिज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि वह कांग्रेस छोड़कर न कहीं जा रहे हैं और न कहीं जाएंगे। कभी बसपा के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे सिद्दीकी ने बसपा प्रमुख मायावती के साथ मुलाकात के दावों को भी खारिज किया है। बसपा में जाने की अटकलों के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बुधस्तिवार को एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी बात रखी है। सिद्दीकी ने कहा कि मेरी बसपा अध्यक्ष मायावती से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। मेरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी कांग्रेस पार्टी के साथ है और मैं आजीवन अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी है एक जमाने में बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा अध्यक्ष मायावती के बेहद खास माने जाते थे। वह मायावती सरकार में ताकतवार मंत्री रहे। 2008 में मायावती से कुछ मसलों पर अनबन होने के बाद वह अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें बीजे लोकसभा चुनाव में बिजनौर से लड़ाया था लेकिन वह पराजित हो गए। वर्तमान में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं।

सिडबी ने 1000 करोड़ के वलस्टर डेवलपमेंट फंड को दी मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टरों में ठोस बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 1000 करोड़ रुपए के सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की है। इस सहायता से राज्य में एमएसएमई समूहों के विकास को गति मिलेगी। सरकारी प्रकवा ने बताया कि फंड के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा उन पात्र परिवारियाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी जिन्हें एससीडीएफ सहायता के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जाना है। क्लस्टर बुनियादी ढांचों को सहायता प्रदान

छह हजार केंद्रों पर आज से गेहूं खरीद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश मे कल पहली अप्रैल से 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद एक शुरु होगी। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति कुन्तल तय किया है। खरीद का लक्ष्य 60 लाख मिट्टिक टन रखा गया है। गेहूं की खरीद के लिए किसानों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा लेकिन धान बेंचने के लिए विपणन वर्ष 2021-22 में जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उन्हें अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लाक करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी क्रय केन्द्र पर गेहूं बेंचने में किसानों के समक्ष कोई समस्या नही आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि क्रय केन्द्रों का चयन इस प्रकार किया जाए ताकि किसानों को अपना गेहूं बेंचने के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े। भंडारण

गोदामों और क्रय केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि गेहूं की खरीद सीधे किसानों के माध्यम से की जाये और जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों से गेहूं ह्यूमनत समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति कुन्तल से कम दर पर क्रय न किया जाय तथा गेहूं क्रय में विचौलियों को संलिप्तता कदापि न हो। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी।

सरकार ने 60 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि खरीद विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी, केवल अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लांक करना होगा।

दुबई में 9 से 12 मई तक ब्राडिंग व मार्केटिंग कार्यक्रम में शामिल होगा पर्यटन विभाग



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग द्वारा आगामी 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हालांकि खरीद विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी, केवल अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लांक करना होगा।

निर्देश दे दिये गये है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता को गम्भीरता से लिया जायेगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि आगामी 100 दिनों के अन्तर्गत 5 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध पर्यटन स्थलों पर भव्य आयोजन कराये जायेंगे। इसके अलावा जून में ट्रेवल राइट्स ट्रेवल ब्लागर्स एवं टूर अपरेटर्स का अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्लेव आयोजित किया जायेगा। श्री सिंह ने यह भी बताया कि मई में ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात सोशल मीडिया ब्लागर्स के लिए फैन टूरस का आयोजन किया जायेगा।

इसके अलावा पर्यटन स्थलों की ब्राडिंग एवं मार्केटिंग के लिए अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई में 9 मई से प्रतिभाग किया जायेगा। 19 अगस्त को मथुरा में कृष्णोत्सव को भव्य रूप से मनाये जाने की कार्य योजना बनायी जायेगी तथा 14 जूनको कबीर उत्सव का भव्य आयोजन किया जायेगा।

ईंधन की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए सरकार: मायावती



लखनऊ। देश के पांच राज्यों में सरकारों के गठन के बाद तेजी से आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईंधन की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए। गुरुवार को टीवीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि देश के पांच राज्यों में विधानसभा आमचुनाव सम्पन्न होने के बाद अब तक उप्र सहित पूरे देश में डीजल पेट्रोल आदि के कई बार दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी सीधी मार गरीब एवं मध्यम वर्गों पर पड़ रही है। केन्द्र सरकार इसे कम करने हेतु उचित कदम जरूर उठाये।

महंगाई भारत मुक्त अभियान के तहत कांग्रेस ने किया प्रदर्शन



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस ने महंगाई भारत मुक्त अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में भाजपा सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार को देश के नागरिकों से धोखेबाजी, विश्वासघात और छल के खिलाफ घरो के बाहर गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर माला पहनाकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पीएनजी और सीएनजी का दाम लगातार बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस के

मीडिया संयोजक और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ और आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। प्रदर्शन के प्रथम चरण में आज कांग्रेस नेताओं- कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने महंगाई के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर मार्च कर विरोध किया तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा और बरेली, मुरादाबाद, शाहजहापुर, लखीमपुर, सीतापुर लखनऊ, बाराबंकी सहित सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मनोज यादव ने लखनऊ हाइकोर्ट पर प्रदर्शन किया। लखनऊ में जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश त्रिपाठी व युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगे सिलेंडर पर माला चढ़ाई व मोटरसाइकिल पर माला चढ़ाई महंगाई पर जनविरोधी भाजपा सरकार को कोसा। लखनऊ के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व विधायक ईंदल रावत, प्रदेश मीडिया संयोजक व प्रवक्ता अंशु अवस्थी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र मदान, अमरनाथ अग्रवाल सहित भारी संख्या में कांग्रेसजन शामिल रहे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के जरिए हो रोजगार का सृजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक बढ़ावा दें और इन इकाइयों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2017 में सुधार के लिए एक सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों के चयन एवं भर्ती की कार्यवाही शीघ्र नियमानुसार सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को अपने कैप कार्यालय पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मौर्य ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की दिशा में अभिनव प्रयास करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसके लिए ठोस व



प्रभावी रणनीति तैयार कर चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पूरे प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक वास्तविक पात्र लोगों को लाभ दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल का संस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ायी जाए।

रोजगार सृजन मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का योगदान सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता एवं असीमित संभावनाओं के दृष्टिगत

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की व अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण फ ल उद्योग विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का पांचवां संस्करण आज होगा आयोजित

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के पांचवें संस्करण के दौरान दुनियाभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की संकल्पना की जिसमें देश के साथ-साथ विदेशों से भी छात्र, अभिभावक, शिक्षक परीक्षा की वजह से होने वाले तनाव को दूर करने और जीवन को उत्सव की तरह जीने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बातचीत करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो उत्तर प्रदेश में पत्रकारों से बात करते हुए पीआईबी के एडीजी आरपी सोरोज ने केन्द्रीय भवन लखनऊ में पत्रकारों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एरजाम वॉरियर्स का हिस्सा है।

अयोध्या में दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची के परिजन से मिले अखिलेश

● सपा अध्यक्ष ने की एक करोड़ मुआवजे की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अयोध्या में दुष्कर्म की शिकार एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के चाचा और पिता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सपा मुख्यालय में भेंट की और अपना दर्द बयान किया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठ-फरेब की राजनीति करती है। बड़े जोशोर से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा राज में बेटियां सर्वाधिक दुराचार की शिकार हुई हैं। छेड़छाानी से परेशान कई छात्राओं को पढ़ाई छूट गई और कुछ ने तो आत्महत्या तक कर

ली। समाजवादी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए 1090 वृमेन पावर लाइन सेवा शुरू की थी। उसे भी चौपट कर दिया गया। सपा प्रवक्ता ने बताया कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी चौराहा के पास 16 मार्च 2022 को जब रात्रि 8 बजे बच्ची खेल रही थी तभी किसी हैवान ने उसे अपना शिकार बनाया। बच्ची को मारापीटा और धमकाया गया। वह अभी तक सदमें में है। उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ में उसी रात्रि 11 बजे भर्ती कराया गया है। बच्ची के पिता ने बताया कि 16 मार्च की घटना से आज 15 दिन हो गए। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। उसका एक वर्ष तक इलाज चलेगा। बच्ची ने बताया था कि दुष्कर्म की घटना में तीन लोग शामिल थे। अब तक सभी

आरोपितों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सरकार ने परिवार की कोई सुध नहीं ली। अखिलेश यादव ने दुखी परिवार को ढांडस बंधाते हुए कहा कि पवित्र धाम में ऐसी अपवित्र घटना होना दुखद और विचलित करने वाली है। पांच वर्ष की मासूम बच्ची मेडिकल कालेज लखनऊ में तड़प रही हैं पर शासन-प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। अभियुक्त, बचाने में सरकार लगी हुई है। यह निंदनीय है। भाजपा जश्न मनाने में व्यस्त है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की मांग करते हुए सरकार से एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और आजीविका के लिए परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है।

संचारी रोग नियंत्रण को हर दरवाजे पर दस्तक देगी टीम

● दो अप्रैल से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान सिद्धार्थनगर से होगी शुरुआत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार 2.0 ने कोरोना संक्रमण के साथ ही दूसरी बीमारियों को मात देने की तैयारी कर ली है। यूपी में 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा को कहा है। सीएम ने बैठक में कहा कि प्रदेश में आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस अभियान के माध्यम से जागरूकता इलाज और सुविधाओं के उच्चीकरण के साथ साथ

स्टाफ की तैनाती को गति दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर विभाग सभी प्रकार की तैयारियों को समय से पूरा करने के आदेश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों को किसी सिद्धार्थनगर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण और दिव्यांग, कुपोषित बच्चों की खोज के लिए इस प्रकार की कोई समस्या न आए। इस बात को चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस न जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को भी सुनिश्

निधि खर्चने में राकेश राठौर अत्वल और रामकृष्ण फिसड़ी

संवाददाता। सीतापुर

सीतापुर वासियों के लिए चिंता की बात यह है कि उनके 9 विधायक और एक एमएलसी अपनी निधि का 2 करोड़ 11 लाख 60 हजार 47 रूपए खर्च ही नहीं कर पाए, बजट की यह भारीभरकम धनराशि लेप्स हो गई। विधायक निधि का बजट खर्च करने में जहां सबसे आगे सदर से पूर्व विधायक राकेश राठौर रहे, वहीं न बजट खर्च कर पाने वालों में सबसे फिसड़ी मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भांगव का स्थान रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महोली से दूसरी बार भाजपा से विधायक बने शंशांक त्रिवेदी अपनी निधि का 69 लाख 61 हजार 10 रूपए खर्च ही नहीं कर सके। सदर से पूर्व विधायक राकेश राठौर ने अपनी विधायक निधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया। उनकी विधायक निधि में सिर्फ 6 हजार 250 रूपए ही खर्च होने से बचे। हरगांव से दूसरी

● वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक निधि का 2 करोड़ 11 लाख 60 हजार 47 रूपए नहीं खर्च कर पाए माननीय

बार भाजपा से विधायक बने और योगी सरकार के कारागार राज्यमंत्री सुरेश राठी भी 10 लाख 30 हजार 448 रूपए खर्च नहीं कर सके। लहरपुर से पूर्व विधायक सुनील वर्मा 14 लाख 22 हजार 571 रूपए खर्च नहीं कर पाए। बिसवां से पूर्व विधायक महेंद्र यादव का भी ऐसा ही हाल रहा 18 लाख 33 हजार 306 रूपए खर्च नहीं कर सके। सेवता से दूसरी भाजपा के विधायक बने ज्ञान तिवारी विधायक निधि खर्च करने में काफी हदतक सफल रहे, फिर भी 10 हजार 822 रूपए खर्च करने से रह गए। महमूदाबाद से 6 बार

विधायक रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा भी 47 हजार 351 रूपए खर्च नहीं कर सके। सिधौली से पूर्व विधायक डा. हरगोविंद भाग्वं भी 32 हजार 321 रूपए खर्च नहीं कर पाए। विधायकों में मिश्रिख से पांचवी बार विधायक रामकृष्ण भांगव अपनी विधायक निधि का सबसे ज्यादा 86 लाख 51 हजार 736 रूपए खर्च नहीं कर पाए। एमएलसी आनंद भदौरिया भी 80 हजार 232 रूपए खर्च नहीं कर सके, इस तरह से कुल 2 करोड़ 11 लाख 60 हजार 47 रूपए विधायक निधि के लेप्स हो गए, 31 मार्च को यह पैसा लेप्स हो गया। नए वित्ति्य वर्ष में विधायक निधि का जो अनुमन्य बजट आएगा उसमें लेप्स हुआ यह पैसा कटकर सीतापुर को मिलेगा। यानि सीतापुर वासियों को 9 विधायक और एक एमएलसी के विधायक निधि के रूप में मिलने वाले 30 करोड़ रूपए की धनराशि में 2 करोड़ 11 लाख 60 हजार 47 रूपए कम कर दिए जाएंगे।

एसडीएम से आश्वासन पर धरना समाप्त

संवाददाता। सीतापुर

बिसवां एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए बुधवार की देर शाम तहसील परिसर में लेखपाल संघ के बैनर तले बुधवार की देर शाम लेखपाल धरने पर बैठ गए थे। गुरुवार को दोपहर बाद एसडीएम से वार्ता के दौरान आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया। दरअसल, संगठन के तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव व सचिव नीलेश कुमार यादव की अगुवाई में लेखपाल विकास वर्मा के साथ एसडीएम बिसवां द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर अभद्र भाषा करने के आरोप समेत सात सूत्रीय मांगो को लेकर लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांगे माने जाने के आश्वासन पर लेखपालों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मौके पर सौरभ यादव, अमर सिंह, रामकुमार, विनीत सिंह, पूनम समेत दर्जनों लेखपाल मौजूद थे।

जेंडर एक्टिविटी कार्यशाला का आयोजन

सीतापुर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में जेंडर एक्टिविटी कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रशिक्षकों द्वारा बालिकाओं की समस्याओं और अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कार्य योजना तैयार की गई और उसे विद्यालयों में व्यवहार में लाने का संकल्प लिया गया। बीईओ रणजीत कुमार ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार द्वारा बहुत सारे अभियान और कार्यक्रम संचालित है। विद्यालयों में प्रारंभ में हीऐसा वातावरण बताना जाए जिसमें बालक, बालिका में किसी तरह की भेदभाव की भावना विकसित ना हो पाए। इस मौके पर प्रशिक्षक अनवर सिंह, संदर्भदाता अल्पना वर्मा, अनुज वर्मा, संदीप कुमार, पंकज वर्मा, अंजलि वर्मा, सौरभ शुक्ला, रामचंद्र वर्मा जमील अहम, हरगोविंद वर्मा, सेवक राम, हंस दीपक खरे आदि मौजूद थे।

प्रशासन ने मुक्त कराई जमीन, चला बुलडोजर

लखीमपुर खीरी। गुरुवार को प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दिया। तहसील व ब्लॉक लखीमपुर के ग्राम लखीमपुर देहात में भूमि गाटा संख्या 1187 रकबा 0.182 हेक्टेयर से प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटवाया।

एसडीएम सदर राजेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व, विकास व पुलिस विभाग के अफसरों की मौजूदगी में उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। अवैध कब्जे व निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अब चर्चा हो रही है कि जिले में बुलडोजर का अमर दिखना शुरू हो गया है।बताते चलें कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा था पूर्व में कई बार कब्जा हटाने का प्रयास हुआ किंतु पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद अलीम के परिवारवालो के विरोध के चलते कब्जा नही हटवाया जा सका। उक्त भूमि पर प्रशासन द्वारा पंचायत घर



बनवाने के लिए चिन्हित किया गया था।गुरुवार को बीडीओ लखीमपुर की जानकारी व सूचना पर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राजेश कुमार, नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह, बीडीओ पीयूष कुमार सिंह ने चौकी इंचार्ज जेल गेट वा भारी पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा बुलडोजर के माध्यम से हटवाया। अवैध कब्जे की भूमि का मूल्य लगभग 70 लाख रुपए है। कब्जे हटवाने के बाद प्रशासन ने पंचायत भवन की नींव भी खुदवानी शुरू कर दी।

नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित

संवाददाता। सीतापुर

लहरपुर के केसरीगंज क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा औषधनाथ धाम चंदेदुपा में श्री श्याम सेवा संस्थान मानव सेवा चौरिटेबल संस्थान के तत्वावधान में आयोजित नि:शुल्क नेत्र शिविर, सीतापुर आंख अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम द्वारा आयोजित किया गया।

जिसमें डॉक्टर अनुराग पांडेय व सहयोगी टीम द्वारा 300 नेत्र रोगियों का नि:शुल्क परीक्षण किया गया। जिसमें से 82 नेत्र रोगियो को ऑपरेशन योग्य चिन्हित कर संस्थान द्वारा जिला मुख्यालय भेजा गया।

इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष अजय पांडेय सरल, अनूप कुमार पांडेय, प्रधान कोशल किशोर पांडेय, प्रमोद त्रिवेदी आदि लोग मौजूद थे।

गेहूं खरीद अभियान 1 अप्रैल से 15 जून तक

संवाददाता। सीतापुर

जिला पंचायत सीतापुर के नेहरू सभागार में जनपद के सभी क्रय एजेंन्सियों के जिला प्रबन्धक, केन्द्र प्रभारियों की कार्यशाला एडीएम व जिला खरीद अधिकारी राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बताया गया कि गेहूं खरीद की अवधि 01 अप्रैल से 15 जून तक है। जिले में विभिन्न क्रय संस्थाओं के 170 गेहूं कय केन्द्र खुले हैं। समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित है। केन्द्र के खुलने का समय प्रातः 9 बजे से सांय 06 बजे तक है। केन्द्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिवस खुलेंगे। केन्द्र पर गेहूं खरीद हेतु 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोइंग फैन, पावर डस्टर, डबल जाली छलना अनिवार्य रूप से रखे जायेगे। प्रत्येक केन्द्र पर बैनर का प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जायेगा जहाँ पर कृषकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। बैनर में सम्पूर्ण विवरण व टोल फ्री नंबर

18001800150 बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य है। गेहूं खरीद इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफपरचेज (ई-पॉप) मशीन के माध्यम से किसानों से बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण द्वारा की जानी है। जिला खरीद अधिकारी ने निर्देश दिये कि गेहूं खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन माड्यूल पर फीड करना होगा। केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी जो ऑनलाइन फीड होगी। खरीद ऑनलाइन फीडिंग (रियल टाइम) व शत-प्रतिशत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। कृषक की गेहूं खरीद ऑनलाइन टोकन व्यवस्था द्वारा निधारित तिथि पर ही होगी। मंडियों में नीलामी का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि बोली समर्थन मूल्य से कम पर आती है तो अनिवार्य रूप से कम कृषक का माहूँ कय केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। प्रत्येक दिवस में नीलामी प्रक्रिया की शाई वीडियो क्लिप बनाकर जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप पर सम्बन्धित मंडी सचिव प्रेषित करेंगे। साथ ही मण्डी में गेहूं की

आवक का सम्पूर्ण विवरण दैनिक रूप से रजिस्ट्रर में अंकित करेंगे। गेहूं क्रय केन्द्रों पर कृषकों के बैठने के लिए तख्त, कुर्सियाँ, पीने के लिए स्वच्छ पानी, वर्षा से सुरक्षा हेतु त्रिपाल, क्रेटस इत्यादि व्यवस्थाये केन्द्र पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिला खरीद अधिकारी ने गेहूं, क्रय योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से कराये जाने के भी निर्देश दिये। गेहूं का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली द्वारा किया जायेगा। केन्द्र पर, विक्रय के लिए आने वाले किसानों के साथ सीम्य एवं मृदु व्यवहार किया जायेगा। कार्यशाला में सहायक आयुक्त, सहायक निबन्धक सहकारिता नवीन शुक्ला, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविन्द कुमार दुबे, जिला प्रबन्धक पीसीएफपंकज कुमार, जिला प्रबन्धक पीसीयू शशिकान्त मोर्या, जिला प्रबन्धक यूपीएसएस ओपी सिंह, मण्डी सचिव सीतापुर देवेन्द्र प्रताप, विपणन निरीक्षक शान्तनु मिश्र, वैभव मिश्र आदि मौजूद थे।

बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे देश व्यापी प्रदर्शन के क्रम में नगर गोला गोकर्णनाथ के विकास चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अगुआई करते हुए जिला अध्यक्ष प्रह्लाद पटेल व अन्य कांग्रेस जनों ने गैस सिलिंडर, मोटरसाइकिल को माला पहनाकर, केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध किया और सरकार से इस्तीफे की मांग की।

जिला अध्यक्ष प्रह्लाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्तू तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को चार सौ का गैस सिलिंडर भी महंगा लगता था और अब एक हजार रुपये का सिलिंडर भी सस्ता लगता है। महंगाई से मुक्ति और संविधान की रक्षा के लिये काँग्रेस पार्टी सतत संघर्ष कर रही है और जब इस जन विरोधी सरकार को हटा ना दे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। सभी को



संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता अमित गुप्ता ने कहा कि 2014 से लेकर अभी तक भाजपा की केंद्र सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपये पेट्रोल और डीजल पर कर के रूप में जनता से वसूलें हैं द्य इस पैसे को केंद्र सरकार द्वारा किस मद में प्रयोग में लाया गया है ये सरकार जनता को बताएं। जो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। सुरक्षा नहीं दे पा रही। शिक्षा

प्रदर्शन के समापन पर सिलिंडर बजा कर और सरकार विरोधी नारे लगाकर पेट्रोल, डीजल, दवाई के



उद्योग धंधे नहीं लगा पा रही वो जनता की गाढ़ी कमाई का कहा इस्तेमाल कर रही हैं। ये सरकार बतायें। जिला उपाध्यक्ष शिशा खरे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पांच किलो मुफ्त अनाज तो दे रही है लेकिन उस मुफ्त अनाज को पकाने के लिए एक हजार का सिलिंडर कहाँ से आयेगा।

बजर्शन के समापन पर सिलिंडर बजा कर और सरकार विरोधी नारे लगाकर पेट्रोल, डीजल, दवाई के



बढ़ते दाम वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव राम कुमार वर्मा, विश्व रिकॉर्ड धारी यतीश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष सहजेंद्र दीक्षित, जिला महासचिव प्रेम वर्मा, जिला सचिव केके मिश्रा, युवा नेता प्रदीप रघुनायक, दीपक अर्कवंशी, रोहित वर्मा, हरिवंश मोर्य, राम नरेश भांगि, शशीफ अहमद, फकीर मोहम्मद व रविंद्र कुमार शुक्ल आदि काँग्रेसजनों ने सहभागिता की।

अस्पताल जाते समय

हुई प्रसव पीड़ा, एंजुलेंस में हुई डिलीवरी

ढखेरवा खीरी। स्वास्थ्य केंद्र रमियांबेहड़ में आपात सेवा 102 नंबर एंजुलेंस एक बार फिर वरदान साबित हुई है। प्रमोप्रभु से सीएचएससी रमियांबेहड़ ले जाते समय करीब गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर 102 नंबर एंजुलेंस के कर्मियों ने एंजुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव करा कर जच्चा बच्चा की जान बचाई। इसके बाद जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्रसव के बाद महिला के परिजनों ने राहत की सांस ली और एंजुलेंस में मौजूद डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया।मरीज के परिजनों ने 102 एंजुलेंस की सेवा ली एंजुलेंस सही समय पर मिली। मरीज को 102 एंजुलेंस में लेकर गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे चले थे कि मरीज को बहुत देश का प्रसव पीड़ा होने लगा। इस दौरान एंजुलेंस कर्मचारी पायलट पंकज कुमार एवं ईंपटी कुण्ण देव शर्मा जौने मरीज का प्रसव एंजुलेंस में कराया जहां पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सही हैं। एंजुलेंस कर्मचारी द्वारा मरीज को सफलतापूर्वक सीएससी रमिया बेहड़ में भर्ती कराया गया।

परीक्षाफल का किया गया वितरण



संवाददाता। रमियाबेहड़-खीरी।

विकासखंड रमियाबेहड़ के गांव रमिया बेहड़ में स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर कानपुर संभाग में वार्षिक परीक्षाफल का वितरण किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिलााल अहमद के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन किया। उसके बाद परीक्षा फल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें जो बच्चे अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय एवं

तृतीय स्थान मिला उनके उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय की तरफ से उन्हें गिफ्ट एवं प्रधान बिलााल अहमद के द्वारा 101 रूपए देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे। सरस्वती ज्ञान मंदिर के परीक्षा फल वितरण में कक्षा 8 के शुभम मोर्य कक्षा 7 से अंकुश मोर्य कक्षा 6 से करन मिश्रा एवं कक्षा 5 से अनिकेत मोर्य कक्षा 4 से खूब लाल कक्षा तीन से गौरव चौधरी द्वितीय से

सिम्रन वर्मा कक्षा प्रथम से विनायक जयसवाल कक्षा उदय से मोहम्मद उर्फ कक्षा अरुण से अभिशोय मोर्य आदि बच्चों को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु कुमार शुक्ला ने कहा कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाई करने के लिए हमेशा अग्रसर करता हूं। और लक्ष्य बनाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त आचार्यगण अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते नजर आए।

पेज एक का शेष

यदि चीन...

गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता घटाने के यत्ने तलाशते भी देखना चाहेंगे। रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिकी डिप्टी एनएसए दो दिनों की यात्रा पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर मास्को की आलोचना नहीं करने के भारत के रुख पर पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ने की पृष्ठभूमि में उनकी यह यात्रा हुई है। उन्होंने संवाददाताओं के एक छोटे समूह से कहा, हम डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली की अनदेखी करने वाले तंत्र या हमारे वित्तीय प्रतिबंधों में गतिरोध उत्पन्न करने वाले तंत्र को नहीं देखना चाहेंगे। उनकी यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है, जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की अपनी दो दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली के रूसी तेल खरीदने सहित द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल(रूसी मुद्रा)-रुपया भुगतान तंत्र पर चर्चा देखने को मिल सकती है। सिंह ने कहा, हम यह नहीं देखना चाहेंगे कि रूस से भारत के आयात में तीव्र वृद्धि हो क्योंकि यह उर्जा या किसी अन्य निर्यात से जुड़ी होगी जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। सिंह ने रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने के भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर यह कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, भारत की उर्जा और रक्षा उपकरणों की

जरूरत को पूरा करने में मदद करने को तैयार है।

भारत से...

रोकने के लिए लोकातांत्रिक देशों के मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करेंगे।। गौतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कई विदेशी गणमान्य लोगों ने भारत की यात्राएं की हैं। अमेरिका को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह बुधवार को भारत पहुंचे, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बृहस्पतिवार को दौरे पर आए हैं। इस रूस की आक्रमकता का मुकाबला करने और देश पर वैश्विक रणनीतिक निर्भरता को घटाने के लिए एकजुटता चाहती हैं। ब्रिटिश उच्चायोग के बयान के अनुसार, उनका दौरा अगले सप्ताह होने वाली प्रमुख नाटो और जी-7 बैठकों से पहले हुआ है।

दिल्ली में...

किसी भी परिदृश्य से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों को गाढ़ा कम किए बिना सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। मालूम हो कि पिछली डीडीएमए बैठक में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था। फरवरी की शुरुआत में कोरोना संबंधी पाबंदियों में आदेश जारी करके निजी कार में मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था।

नगालैंड, असम...

क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर में 2004 से आफफ्सा लागू है। बृहस्पतिवार के फैसले के बाद मणिपुर के छह जिलों के 15 थाना क्षेत्रों को एक

अप्रैल से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर कर दिया जाएगा। आफफ्सा 2015 में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों की असम से लगती 20 किलोमीटर की पट्टी पर और नौ अन्य जिलों के 16 थाना क्षेत्रों में लागू था। इसका दायरा आहिस्ता-आहिस्ता कम किया गया और अब अरूणाचल प्रदेश के कानूरा राज्य के सिर्फ तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो थाना क्षेत्रों में लागू हैं। पूरे नगालैंड में 1995 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से आफफ्सा हटाने के लिए गठित समिति की सिफारिशों को मान लिया है। नगालैंड के सात जिलों के 15 थाना क्षेत्रों से एक अप्रैल से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटया जा रहा है। नगालैंड में 14 आम लोगों की हत्या ने तानव बढ़ा दिया था जहां लोगों ने आफफ्सा को हटाने के लिए कई हफ्तों तक प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने कहा था कि वह और मणिपुर के लोग चाहते हैं कि आफफ्सा को हटया जाए लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को देखना होगा।

दिल्ली-मेरठ...

वाहनों के टोल का रेट बाकी जिलों में रजिस्टर्ड वाहनों से कम रखा गया है। इस सुविधा से बिजनेस के लिए चलने वाले वाहनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। एचएचआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से ड्रासना तक सफर करने पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा, लेकिन वाहन चालक यदि एनएच-9 से हापुड़ की

तरफ और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से मेरठ की तरफ जाते हैं तो पूरे हिस्से का टोल लगेगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर के माध्यम से होगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। काशीपुर, भोजपुर और रसूलपुर सिकरोड़ के बीच टोल प्लाजा से टोल वसूली की जाएगी, जबकि बाकी जगह पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर के माध्यम से की जाएगी। नई व्यवस्था में प्रतिदिन करीब 30 हजार वाहन चालकों से टोल लिया जाएगा। मतलब, रोजाना दिल्ली और मेरठ के बीच इस एक्सप्रेसवे के जरिए 30,000 से ज्यादा वाहन आवागमन कर रहे हैं।

इमरान और...

(पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जददारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त विपक्ष को खान को सुरक्षित रखा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, निर्वाचित प्रधानमंत्री को बिना किसी और देश के इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह संसद में बहुमत खो चुके हैं। विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के महासचिव अहसान इकबाल ने पीटीआई-भाषा से कहा कि उनकी पार्टी तत्काल नए सिरे से चुनाव चाहती है। उन्होंने कहा, हम नेशनल असंबली का कार्यकाल पूरा होने तक (अगले साल के मध्य तक) इमरान खान का कचरा नहीं ढोना चाहते। यदि संयुक्त विपक्ष एक साल से अधिक समय तक बिना नए जनादेश के सत्ता में रहता है, तो यह खान की तरह अलोकप्रिय हो जाएगा। इकबाल ने कहा कि सिर्फ नए सिरे से चुनाव ही पाकिस्तान को

मौजूदा राजनीतिक संकट से आगे ले जा सकता है। दूसरी ओर इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए संसद के निचले सदन की बैठक बृहस्पतिवार को हुई। सोनिया ने... मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान को कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35 प्रतिशत कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने फोर्सड लेबर माना है। उनके मुताबिक, इसी वर्ष 26 मार्च को, दूसरे सभी राश्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वह (सोनिया) देश की एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सदन में जो विषय रखा है जो पूरी रूप से तथ्यों से परे है। साल 2013-14 में (संप्रग सरकार के समय) मनरेगा का 33 हजार करोड़ रुपए का बजट था, जो आज एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। इनके (कांग्रेस) समय विपक्षी भ्रष्टाचार होता था। इस दौरान कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे। इस पर ठाकुर ने कहा, ए लोग मंत्री की ओर से जवाब देने का विरोध कर रहे हैं। यह दिखाता

है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। बाद में पीठासीन सभापति रमा देवी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने शून्यकाल में जो विषय उठाए हैं, सरकार उसका उत्तर देना चाहे, तो दे सकती है।

हवाई अड्डों...

प्रजातियों में रेड-ईयर स्लाइडर टर्टल को सबसे अधिक संख्या में जल्द किया गया है। इसके बाद चीनी तालाबों में पाया जाने वाला कछुआ मॉर्मिस रीसेडी रहा। इसी तरह, कई वनस्पति प्रजातियों, जिनमें एगरवुड एक्विवालेंट मैलाकॅसिस, रेड सैंडर्स पटरोकार्पस सैंटलिनस, सैंडलवुड सैंटलम एल्बम और औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) जैसे कुछ सौसुरिया कॉर्टस जड़ें भी भारी मात्रा में हवाई अड्डों पर जन्म की गईं। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी का सबसे अधिक सामान पकड़ा गया। उसके बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का नंबर आता है। हवाई अड्डों के माध्यम से तस्करी बढ़ने से वन्यजीवों को अधिक खराब पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इंडिया प्रमुख अतुल बर्माई ने कहा कि सीमा शुल्क, सीआईएएएफ और वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूसीसीबी) समेत अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ साझेदारी की है, ताकि वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए ठोके कार्यक्रम बनाया और उसे लागू किया जा सके। डब्ल्यूसीसीबी के अतिरिक्त निदेशक तिलोत्तमा वर्मा ने कहा कि कम यात्रा समय और व्यापक पहुंच के कारण हवाई अड्डे वन्यजीवों की तस्करी प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं।

अधिकरण ने जाकिर नाइक के आईआरएफ पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाने की पुष्टि की

भाषा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अधिकरण ने इस्लामिक रिसर्च फ़ाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल बढ़ाने की पुष्टि की है। आईआरएफ की स्थापना जाकिर नाइक ने की है जो फरार हैं और उसपर भारत और विदेश के मुस्लिम युवाओं को आतंकी कृत्य करने के लिए उकसाने का आरोप है। केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून 1967 के तहत पहली बार आईआरएफ को प्रतिबंधित किया था। सरकार ने 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बात पर फैसला करने के लिए 13 दिसंबर 2021 को एक अधिकरण गठित क था कि आईआरएफ को गैर

कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। इस अधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि इस अधिकरण ने नौ मार्च 2022 को एक आदेश पारित करके आईआरएफ को गैर कानूनी संगठन घोषित किए जाने की पुष्टि की। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि वह केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दी गई दलीलों से 'पूर्ण सहमति' हैं और यह दिखाने के लिए सामग्री है कि आईआरएफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था। अधिकरण ने कहा कि आईआरएफ उन गतिविधियों में शामिल है जो न केवल युवाओं को भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से गैरकानूनी गतिविधियों को करने के लिए

उकसाती है, बल्कि देश के खिलाफ असंतोष पैदा करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह है कि संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जाए। उसने कहा कि सबूतों के अवलोकन करने से पता चलता है कि "डॉ. जाकिर नाइक के कार्य और आचरण भारत के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हैं। यह आदेश 30 मार्च को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

अधिकरण ने आईआरएफ की इस दलील को खारिज कर दिया कि 2016 में प्रतिबंध लगने के बाद, उसने ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जो देश के राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हो और जहरी है कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि आईआरएफ और उसके पदाधिकारियों ने गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखा है जो गृष्टहित के लिए हानिकारक हैं।' उसने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न केवल डॉ नाइक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं बल्कि विभिन्न खाड़ी देशों में अपनी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार भी करते रहते हैं। प्रतिबंध की मियाद बढ़ाते हुए मंत्रालय ने कहा था कि अगर आईआरएफ की गतिविधियों पर लगाम नहीं कसी गई और उसे तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो उसे अपनी विनाशक गतिविधियों को जारी रखने का मौके मिलेगा और वह अपने लोगों को फिर से जमा कर सकता है जो अब भी फरार हैं। उसने कहा था कि केंद्र सरकार की राय है कि आईआरएफ की गतिविधियों के संबंध में, यह जरूरी है कि उसे फौरन गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। मुंबई में जन्मे नाइक ने एक जुलाई 2016 को ढाका के एक केफे में हुए विस्फोट के महेनजर भारत छोड़ दिया था।



नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री पीरूष गोयल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़म, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह 72 संसदों की विदाई समारोह में शिरकते करते हुए

ईडी ने धन शोधन मामले में नागपुर के वकील, उनके भाई को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, नागपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को नागपुर के वकील सतीश उदेशे और उनके भाई प्रदीप को धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया और शुरुवार को अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। वकील ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह करीब छह बजे नागपुर के पार्वती नगर इलाके में उनके आवास पर छापा मारा। छापेमारी करने वाली टीम के साथ सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मी भी थे। अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों भाइयों के खिलाफ धन शोधन का मामला कुछ समय

पहले नागपुर में लगभग 1.5 एकड़ जमीन की खरीद से संबंधित है और जमीन की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज कथित तौर पर जाली थे। उन्होंने कहा कि खरीदी गई जमीन भाइयों के नाम पर थी। बाद में वकील और उनके भाई को दिन में करीब 11 बजे पृष्ठताछ के लिए शहर के सेमिनरी हिल्स इलाके में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईडी की टीम सतीश उके का लैपटॉप, कुछ दस्तावेज और उनके परिवार के चार सेलफोन साथ में जांच के लिए ईडी कार्यालय ले गई।

वकील ने भाजपा नेताओं, खासकर फडणवीस के खिलाफ अदालतों में कई याचिकाएं दायर कर रखी है। एक याचिका में वकील ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के अलावा फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का अनुरोध किया था।



जयपुर में गुर्जर नेता किरोरी सिंह बैसला की लम्बी बीमारी के बाद मौत हो गई। श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

मोदी से मिले स्टालिन, श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच राज्य सरकार द्वारा वहां रह रहे तमिलों को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र की अनुमति मांगी। स्टालिन ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्हें एक विस्तृत ज्ञान सौंपा, जिसमें द्वीपीय देश में आर्थिक संकट से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे।

श्रीलंकाई तमिलों द्वारा झेली जा रही मुश्किलों का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा कि इनमें से कई तमिलनाडु की दूधर यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि द्वीपीय देश में जरूरी वस्तुओं की कीमतें उनकी पहुंच के बाहर हो गई हैं और वे राज्य में एक ट्रांजिट लिबरि में रह रहे हैं। ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है कि

श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच राज्य में वहां से और लोग भी आ सकते हैं। इस पड़ाव पर तमिलनाडु सरकार एक जीवनरक्षक उपाय के तौर पर गंभीर खाद्य संकट से जुड़ा रहे श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग में रह रहे तमिलों तथा वहां के बागानों में रह काम करने वाले मजदूरों को जरूरी वस्तुएं व जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध करने की इच्छुक है। तमिलनाडु सरकार श्रीलंकाई महिलाओं व बच्चों सहित अन्य संवेदनशील समूहों की मदद करने की भी इच्छुक है। इसमें कहा गया है, प्रोपेकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। स्टालिन ने सुबह संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। दिल्ली में स्टालिन का स्वागत करते हुए सोनिया उनसे मिलने संसद परिसर में बन रहे द्रमुक कार्यालय पहुंचीं।

सोनिया ने कहा कि वह स्टालिन को वणक्कम कहते आई हैं और दो अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आगमन के लिए केंद्र सरकार से उनसे दोबारा मिलेंगी। स्टालिन ने एक शॉल भेंटकर उनका आभार जताया। द्रमुक प्रमुख तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए हैं और इस दौरान उनके कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने की संभावना है। पार्टी संसद कनिमोई ने बताया कि द्रमुक दो अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेगी और इस अवसर पर उसने भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। मोदी के सामने तमिलनाडु के मछुआरों से संबंधित मुद्दे उठाते हुए स्टालिन ने केंद्र से भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के स्तर की वार्ता की व्यवस्था करने का आग्रह किया, जो 2016 के बाद से नहीं हुई है, ताकि मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी

नौकाओं की जब्ती की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। 1974 में श्रीलंका को सौंपे गए कच्चातीव्र को वापस लाना और पाक खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों को बहाल करना इस समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित करेगा। कावेरी नदी पर कर्नाटक सरकार को मेकेदातु परियोजना को लेकर स्टालिन ने प्रधानमंत्री से जेल शक्ति मंत्रालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह इस परियोजना का कावेरी घाटी में कर्नाटक की किसी भी नई जलाशय परियोजना को अपनी मंजूरी न दे। उन्होंने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को मेकेदातु परियोजना को अस्वीकार करने और तमिलनाडु की सहमति के बगैर किसी नई परियोजना का निर्माण शुरू न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह कहते हुए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जा सकता है।

एचसीएल वनीकरण में करेगा मदद

नोएडा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की सीएसआर शाखा एचसीएल फ़उंडेशन एचसीएलएफ ने अपने एन्वयरन्मेंट एक्शन प्लैंगशिप प्रोग्राम एचसीएल हरित के तहत एलडी के साथ ग्रीन एरिया ग्रीन कनेक्टर का वनीकरण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर लखनऊ में हस्ताक्षर किए। यह एमओयू देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण और पक्षियों, मधुमक्खियों तथा अन्य जानवरों की आवासीय जगहों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस साझेदारी के माध्यम से एचसीएलएफ जैव विविधता को पनपने में मदद करते हुए शहर के फेफड़े कहे जाने वाले क्रिमानव्यन के लिए जुलाई 2021 में एक आदेश पारित किया। उसने एमबीसी को दिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण को विभाजित कर दिया था और जातियों को फिर से समूहों में बांटेकर तीन अलग श्रेणियों में विभाजित किया तथा वनियार को 10 प्रतिशत उप-आरक्षण मुहैया कराया था। वनियार को पहले वनियाकुल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था।

नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार आबादी पर बिना मात्रात्मक आंकड़ों के वनियार को आरक्षण देने वाला ऐसा कानून नहीं ला सकती है। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले साल फरवरी में वनियार समुदाय को 10.5 फीसदी आरक्षण देने के तत्कालीन सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक द्वारा पेश किए विधेयक को पारित कर दिया था। मौजूदा द्रमुक सरकार ने इसके क्रिमानव्यन के लिए जुलाई 2021 में एक आदेश पारित किया। उसने एमबीसी को दिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण को विभाजित कर दिया था और जातियों को फिर से समूहों में बांटेकर तीन अलग श्रेणियों में विभाजित किया तथा वनियार को 10 प्रतिशत उप-आरक्षण मुहैया कराया था। वनियार को पहले वनियाकुल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था।

संविधान और अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए: ज्ञानेंद्र अरागा

भाषा। कोय्ल

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हलाल विवाद के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान और अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए। दरअसल कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने हिंदुओं से होसा तड़कू महोत्सव के दौरान हलाल मांस का इस्तेमाल नहीं करने का अनुरोध किया है।

मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुसलमानों के एक वर्ग ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। न्यायालय ने कक्षाओं में स्कूल में वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने की उड़ुपी गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था।

ज्ञानेंद्र ने यहां पत्रकारों से कहा,

जो लोग भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करते और कहते हैं कि अदालत का फैसला उन पर लागू नहीं होता, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। हम उन्हें विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि आपको इस देश में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। कोई भी आपसे नफरत नहीं करता और हमें भाइयों की तरह रहना है।

मंत्री ने कहा कि हलाल से संबंधित मुद्दे पर सरकार की सीमित भूमिका है, जिसे लोगों की समझ पर छोड़ दिया गया है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि हलाल भोजन का बहिष्कार अभियान कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, जिसे हर कोई जानता है। एक अप्रैल को मनाए जाने वाले उगाड़ी उत्सव के एक दिन बाद हिंदुओं का एक वर्ग जो मांसाहारी भोजन करते हैं, वे होसा तड़कू का आयोजन करते हैं। जहां वे मांस पकाते हैं।

गुजरात: नेहरू के बारे में पूर्व उपमुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद विधानसभा में हंगामा

गांधीनगर। गुजरात विधान सभा में भाजपा के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बारे में टिप्पणी की, जिसपर विपक्षी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायकों ने पटेल की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने का श्रेय नेहरू को नहीं दिया जा सकता। पटेल के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और प्रश्न काल के दौरान वेल के निकट एकात्रित हो गए। जब जल संसाधन मंत्री रश्मिकेश पटेल ने कांग्रेस पर सरदार सरोवर बांध परियोजना में देरी करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस विधायक सो.जे. चावड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद 85 मीटर उंचा बांध बनाया था।

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के एक बंकर पर बुर्का पहने महिला द्वारा पेट्रोल बम फेंके जाने ने आतंकी समूहों की हताशा को उजागर किया है। आतंकवादी घाटी में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की कारवाई का सामना कर रहे आतंकी समूह अब हथगोले फेंकने, कूरियर के तौर पर काम करने जैसे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं। हनाफिया स्कूल से 10वीं की पढ़ाई करने वाली अख्तर को 2021 में जम्मू

विवक न्यूज

देश, प्रधानमंत्री और शाह पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में कत्वाली गायक के खिलाफ मामला दर्ज

नोपाल, रीवा (मग़)। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तरप्रदेश के कत्वाली गायकशरीफ परवान के खिलाफ रीवा जिले ने एकसंगीत कार्यक्रम के दौरान देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वधित व्च से भड़कउट्टिपणी करने के आरोप ने मामला दर्ज किया है। शरीफ ने रीवा जिले के मनगवा कस्बे ने उस के दौरान आयोजित कार्यक्रम में 28 मार्च को यह वधित टिप्पणी दी थी, जिसव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी बीच, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को संगीत क्वाकस्बे को चेतावनी जारी करते हुए व्च कि भारत के खिलाफ किसी भी गाने को बर्दस्त नहीं किया जाएगा और उन्हें पहले देश को ध्यान ने रखना चाहिए क्योंकि वे्द्र ने अब राष्ट्रवादी सरकार है। वीडियो ने शरीफ परवान को वधित तौर पर यह कस्ते हुए सुना जा सकता है, मोदी जी कस्ते है हम है, योगी जी (उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) कस्ते है हम है, अमित शाह जी कस्ते है हम है, लेकिन ए है चौन? अगर गरीब नवाज चाह ले तो पता ही नहीं चलैगा कि हिनूदूतान क्क पर बचा था, क्क पर है। मिश्रा ने गोपाल से संवाददाताओं से बताया, इस प्रकरण ने कत्वाल शरीफ परवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 153 और 298 के तहत मामला दर्ज हो चुक है। हमारी दो टीने वानपुर उनक्बे गिरफ्तार कस्ते के लिए पहुंच चुकी है। वानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने संगीत क्वाकस्बे को चेतावनी जारी करते हुए व्च, ऐसे लोगों से तैय यही कस्ना है किचाहे कोई कत्वाली गाए, दुमरी गाए, दादरा गाए (भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली) या कुसु भी गाए, लेकिन देश के खिलाफ गाने वा ख्याल ही निकल दे, क्योंकियह राष्ट्रवाज वा युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है। इस तरह नहीं चलैगा। रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अग्रोधक शिव कुमार वर्मा ने बताया, शरीफ एवं इस कार्यक्रम के आयोजक उस ईदगाह क्कोटी मनगवा के खिलाफ मनगवा पुलिस थाने ने यह मामला बुधवार को दर्ज किया गइल। कई सोशल मीडिया उद्योगक्वकों और गाजपा नेताओं ने शरीफ की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है।

चित्तौड़गढ़ में 12 किलो विस्फोटक बरामद, तीन गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के निबाड़ेज कस्बे ने एक वाहन से 12 किलोग्राम विस्फोटकसम्पत्ती जब्त किया है तथा इस सिलसिले ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पांच अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनने दो मध्यप्रदेश केरहने वाले है। इस मामले ने गजब वाना भी मध्य प्रदेश ने पजीकू है। पुलिस के आतक्वाद निरोधक दस्ते व विशेष कार्यबल (एटीएस-एसओजी) ने बृहस्पतिवार को एकवाहन ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार, निबाड़ेज सदर पुलिस थाना क्षेत्र ने नाबख्ती के दौरान एकसंदिध वाहन को रोव गया और इसकी तलाशी ली गई, जिसने कुल 12 किलोग्राम विस्फोटक, बैटरी केसाथ तीन ऑपरेटिंग घड़ी व तार केसाथ तीन क्कोवरट आदि बरामद हुए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है एवं मामले की जांच आतक्वाद निरोधकदस्ते (एटीएस) द्वारा की जा रही है। इस सिलसिले ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पांच अन्य को हिरासत में लिया गया है, जिनने ने दो व्यतिक्त मध्य प्रदेश केरतलान केरहने वाले है, जिनसे वहां वी एटीएस पूछताछ कर रही है। राजस्थान ने गिरफ्तार व दस्तवाब किए गए आरोपियों को जयपुर लाया गया है। आरोपियों की पश्चात उजागर नहीं वी गई है और अभी यह भी पता नहीं चल है कि ए किस आतंकी संगठन से जुड़े है।

श्रीलंकाई नौसेना ने तीन भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

रत्नेश्वरन (तमिलनाडु)। श्रीलंका की नौसेना ने अपने समुद्री क्षेत्र ने मछली पकड़ने के आरोप ने तीन भारतीय मछुआरे क्कआरो को गिरफ्तार किया है जो तमिलनाडु केरहने वाले है। कल्य वानान वितानन केएक अधिकरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि ए गिरफ्तारिजा बुधवार देर रात वी गई, जब घुडुकोर्टई जिले के तीन मछुआरे क्कआतीव्र के समीप मछली पकड़ने गए थे। एक नौच वी जब वी गई है। इस घटना से दो दिन पहले ही श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा केवधित उल्लंघन के लिए चार मछुआरो को गिरफ्तार किया था और उनकी नौच जब्त वली थी। मछुआरे केप्रतिनिधियों ने ताना घटना पर आक्से जताया है और वे इस मुद्दे का स्थाई समाधान चाहते है।

बोम्बई श्रद्धालुओं पर हमले के बाद अंध के अधिकारियों के संपर्क में

बेगलूर आंध्रप्रदेश के कुसूलु जिले वी मंदिर नगरी श्रीरैलम ने मल्लिकार्जुन मंदिर के आसपास विद्रोआ एवं कर्नाटककेश्रद्धालुओं केबीच हिंसकझड़ केबाद कर्नाटककेमुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने व्च है किउन्हेने अपने समक्च वाईएस नगननोवेलन देव्डी से श्रद्धालुओं वी स्था क्काने वा अनुरोध किया है। बोम्बई ने यक्ष संवाददाताओं से व्च, श्रीरैलम ने कर्नाटक के श्रद्धालुओ पर हमला किया गया। अन्य क्कयो से बड़ी संख्या ने श्रद्धालु तीर्थयात्रा पर जाते है। बास्र केश्रद्धालुओ केलिए उपरुक्त सुविधिधित वी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने व्च किनहसराद एवं कर्नाटकसे बड़ी संख्या ने श्रद्धालु श्रीरैलम जाते है। उन्हेने व्च, नै बुधवार रात से ही आंध्रप्रदेश केअधिकारियों केसंपर्क ने हू।

रूसी हमले के खिलाफ सुरक्षा अहम मोड़ पर है : राष्ट्रपति

एपी। कीव

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के आक्रमण के खिलाफ अपने देश की सुरक्षा को अहम मोड़ पर बताते हुए एक बार फिर अमेरिका से अधिक मदद देने का अनुरोध किया। उनका यह बयान तब आया है कि जब रूस की सेना अपने अभियान को कम करने के वादे से पीछे हटती दिखाई दे रही है।

रूसी सेना ने कीव और उत्तरी शहर चेर्नोहीव के आसपास के इलाकों में बमबारी की तथा बुधवार को देश के अन्य हिस्सों में हमले तेज कर दिए, जिससे युद्ध खत्म करने की ओर किसी भी प्रगति को लेकर संदेह पैदा हो गया है। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डेविड अराखमिया ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता डिजिटल माध्यम से शुक्रवार को बहाल होने की उम्मीद है। इस बीच, यूक्रेन की संसद के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायता बढ़ाने के लिए अमेरिका पर जोर देने के वास्ते वाशिंगटन को यात्रा



की। उन्होंने कहा कि उनके देश को और सैन्य उपकरण, और वित्तीय सहायता तथा रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की आवश्यकता है। यूक्रेन की संसद की सदस्य एनेस्तासिया रेंडिना ने यूक्रेन के दूतावास में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें रूसी सैनिकों की अपनी सरजमीं से खदेड़ने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के समक्ष सीधे यह मांग रखी। उन्होंने देश को रात को

रूस को रोकने के लिए और मदद की आवश्यकता है: जेलेंस्की

कीव (एपी)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद देने का संकल्प जताने के लिए व्हाइट हाउस का आभार व्यक्त किया लेकिन साथ ही कहा कि वह रूसी आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेन को अधिक सहायता दिए जाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात करने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने बुधवार रात को देश को दिए गए एक

वीडियो संबोधन में कहा, अगर हम आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वास्तव में मिलकर लड़ रहे हैं तो हमारे पास इस मुश्किल अहम मोड़ पर मदद मांगने का अधिकार है। टैंक, विमान, तोप प्रणालियां। जेलेंस्की ने कहा कि रूस से बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक के लिए वे बिना कुछ स्पष्ट किए केवल बातें किए जा रहे हैं।

यूक्रेन-रूस के बीच समझौते के लिए वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज फिर होगी शुरु

इस्तांबुल (एपी)। यूक्रेन और रूस के बीच संभावित शांति समझौते के लिए वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने यह जानकारी दी। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एवं संसद में सत्तारूढ़ पार्टी का नेतृत्व करने वाले डेविड अराखमिया ने बताया कि प्रतिनिधिमंडलों ने दो सप्ताह तक वीडियो के जरिए वार्ता करने के बाद

मंगलवार को इस्तांबुल में प्रत्यक्ष रूप से आमने-सामने मुलाकात की थी। अभी तक हुई बातचीत में एक संभावित शांति समझौते की धुंधली रूपरेखा उभरती दिखाई है। इसमें, यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के विचार को त्यागने जैसी रूस की कई मांगों को मानने को लेकर सहमति जताई है।

वीडियो संबोधन में कहा, अगर हम वास्तव में आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे पास इस मुश्किल, अहम मोड़ पर मदद

मांगने का अधिकार है। टैंक, विमान, तोपों की आवश्यकता है। उन्होंने कीव में बेहद कम रेशनी में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर खड़े होकर देश को



यूक्रेन के मारियापोल में ठसी हमले के बाद मलबे से बस्तुओं को निकालने का प्रयास करता एक स्थानीय निवासी

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही यूरोप में किया गया था साइबर हमला

मॉस्को (एपी)। यूरोप में हजारों मॉडेम को प्रभावित करने वाले और यूक्रेन की सेना तथा सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रह नेटवर्क पर साइबर हमले के लिए साफ़ूवेयर कमांड का इस्तेमाल देश पर रूस के आक्रमण करते ही किया गया था। उपग्रह (सेटेलाइट) के स्वामित्व वाली कंपनी ने बुधवार को यह खुलासा किया। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। अमेरिका स्थित वायासेट के मालिक ने साइबर हमले के संबंध में पहली बार जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया और बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के सबसे गंभीर ज्ञात साइबर हमले के बारे में कैसे पता चला। इस व्यापक हमले ने पोलैंड से लेकर फ्रांस तक के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया। मध्य यूरोप में हजारों विंडोव्स10 तक पहुँच बाधित होने से हमले की जानकारी मिली।

दो अरब लोग आज संघर्षरत क्षेत्रों में रह रहे हैं : संरा प्रमुख

एपी। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को कहा कि दो अरब लोग आज संघर्षरत इलाकों में रह रहे हैं और दुनिया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से सबसे अधिक हिंसक संघर्षों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस ने यमन, सीरिया, म्यांमा और सूडान से लेकर हैती तक संघर्षों का हवाला दिया तथा कहा, और अब यूक्रेन में युद्ध सीमाओं से बाहर फैल रहा है और इससे अनाज, ईंधन और ज्वरकों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा आयोग से कहा कि पिछले साल आठ करोड़ 40 लाख लोगों को संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और इसमें यूक्रेन युद्ध शामिल नहीं है, जिसके

कारण पहले ही 40 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं और 65 लाख लोग देश में ही विस्थापित हुए हैं। गुतेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस साल कम से कम 27.4 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि यह 2021 से 17 प्रतिशत अधिक है और इसके लिए 41 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जनवरी में आयोग को एक रिपोर्ट में दो अरब लोगों के संघर्षरत देशों में रहने का हवाला भी दिया। उन्होंने दुनियाभर में बढ़ते सैन्य तख्तापलट और सुरक्षाबलों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने, बढ़ते परमाणु हथियार, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और संघर्षों से अपराधियों तथा अतंकवादी समूहों को हो रहे फायदे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संघर्षों का बहुत कम राजनीतिक समाधान देखा गया, जिसमें कोलंबिया उल्लेखनीय अपवाद है।

आईईएफ प्रमुख ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र का किया दौरा

विएना (एपी)। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईईएफ) के प्रमुख ने बुधवार को दक्षिण यूक्रेन के एक परमाणु संयंत्र का दौरा किया। इस दौरे का मकसद यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात करना और तकनीकी सहयोग मुहैया कराना है। आईईएफ के प्रमुख रफेल मारिनो ग्रोसी ने कहा कि आईईएफ रूस के साथ राजनयिक वार्ता में शामिल नहीं है। ग्रोसी ने कहा, स्थिति शीघ्र पूर्ववत हो और प्रतिष्ठान फिर से यूक्रेनियों के हाथों में आएँ, हम इसके लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन में चार परमाणु संयंत्रों में 15 परमाणु रिएक्टर हैं, जिसमें से एक संयंत्र (जापोरिझिया) रूसी सेना के नियंत्रण में है। इस पूर्वी यूरोपीय देश में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र भी है जहां 1986 में भीषण परमाणु दुर्घटना हुई थी। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया। मंगलवार तक यहां आठ रिएक्टर काम कर रहे थे और शेष को खरखराव के लिए बंद कर दिया गया है।

रूसी राष्ट्रपति का यूक्रेन पर आक्रमण एक रणनीतिक भूल: व्हाइट हाउस

भाषा। वाशिंगटन

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केट बेडिंगफील्ड ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण एक रणनीतिक भूल है, जिसने रूस को वैश्विक मंच पर अलग-थलग कर दिया है। बेडिंगफील्ड ने कहा कि अमेरिका को जानकारी मिली है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना द्वारा गुमराह किया हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे लगता है उनके सैन्य नेतृत्व के बीच पुनरांतर तनाव बना हुआ है।

बेडिंगफील्ड ने एक दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारा मानना ​​है कि पुतिन को उनके सलाहकारों द्वारा इस संबंध में गलत सूचना दी जा रही है कि रूसी सेना किटना खराब प्रदर्शन कर रही है और रूसी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से कैसे पंगु बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके वरिष्ठ सलाहकार उन्हें सच बताने से

बहुत डरते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पुतिन का युद्ध एक रणनीतिक भूल है, जिसने रूस को लंबे समय के लिए कमजोर बना दिया है और विश्व मंच पर वह अलग-थलग पड़ गया है। बेडिंगफील्ड ने कहा कि आक्रमण की शुरुआत में रूस कीव की ओर आक्रमकता से बढ़ रहा था, लेकिन अब वह सार्वजनिक रूप से अपने आक्रमण के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, जो पहले से अलग है। पुतिन को उनकी सेना द्वारा गलत जानकारी देने की अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों को सार्वजनिक करने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जानकारी सार्वजनिक करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका यह कदम एक रणनीतिक भूल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि राष्ट्रपति जो बाइडन रूस में शासन परिवर्तन की नीति की वकालत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ दिन

पहले उन्होंने जो कहा था वह स्वाभाविक आक्रोश से भर बयान था, हमारे पास शासन परिवर्तन की औपचारिक नीति नहीं है। हम केवल रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रूस अपनी गलती का परिणाम भुगतें। पुतिन ने खुद भी कहा है कि प्रतिबंधों का प्रभाव काफी अधिक होगा। इसलिए, हम यूक्रेन को सुरक्षा सहायता प्रदान करने और रूस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गौतलब है कि बाइडन ने पिछले सप्ताह एक भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा था कि यह शख्स सत्ता में नहीं रह सकता। इसके बाद, व्हाइट हाउस और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि बाइडन असल में पुतिन को बेदखल करने के बारे में बात नहीं कर रहे थे।

नेपाल के मंत्री ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन किया

काठमांडू (भाषा)। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर अधिकतर आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने काठमांडू में वलंड हिंदू फेडरेशन की दो दिवसीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर विचार किया जा सकता है और अगर ऐसी मांग आती है तो वह एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। मंत्री अले यहां कार्यक्रम के दौरान वलंड हिंदू फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांग का जवाब दे रहे थे। कार्यकारिणी परिषद की बैठक में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन सहित 12 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि पांच दलों के गठबंधन वाली मौजूदा सरकार को संसद में दो तिहाई बहुमत प्राप्त है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को जनमत संग्रह में रखा जा सकता है। अले ने सवाल किया, हमारे संविधान ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है लेकिन अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है तो जनमत संग्रह के माध्यम से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया।

मुनाफावसूली से सेंसेक्स 115.48 अंक टूटा

● 2021-22 में दिया 18 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न

भाषा। मुंबई

घरेलू शेयर बाजार वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को शुरुआती बढ़त को गंवते हुए अंत में नुकसान के साथ बंद हुए। तीन दिन की तेजी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में मुनाफावसूली से बाजार नीचे आया। तीस शेरों पर आधारित सेंसेक्स वायदा एवं विकल्प खंड में मासिक सौदों के निपटान के अंतिम दिन उतार-चढ़ाव के बीच 115.48 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,568.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह उत्रे में 58,890.92 अंक तक गया और नीचे में 58,485.79 अंक तक आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 33.50 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ



17,464.75 अंक पर बंद हुआ। पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बीएसई सेंसेक्स 9,059.36 अंक यानी 18.29 प्रतिशत, जबकि एनएसई निफ्टी 2,774.05 अंक यानी 18.88 प्रतिशत मजबूत हुआ। एलकेपी सिन्क्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंरानाथन ने कहा, हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के

अंतिम दिन बाजार नरम रहा लेकिन इस साल निफ्टी ने करीब 19 प्रतिशत का लाभ दिया है। वहीं दो खंडवार सूचकांक...थातु और मीडिया ने 50 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया। उन्होंने कहा, मिडकैप- 100 और स्मॉलकैप- 100 ने इस साल 25 प्रतिशत रिटर्न दिया। यह लाभ तब मिला है जब

एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) ने बाजार से काफी बिकवाली की। यह विभिन्न चुनौतियों के बीच घरेलू निवेशकों के भरोसे को बताता है। सेंसेक्स के तीस शेरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. 1.46 प्रतिशत नीचे आया। इसके अलावा विप्रो (1.44 प्रतिशत), डॉ. रेड्डीज (1.04 प्रतिशत) भी नुकसान में रहे। एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस में भी गिरावट रही।

दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलिवर लि. सबसे अधिक 1.66 प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा (1.59 प्रतिशत), इंडसइंड बैंक (0.93 प्रतिशत), भारती एयरटेल (0.80 प्रतिशत), आईटीसी (0.66 प्रतिशत) और टाटन 0.5 प्रतिशत लाभ में रहे। सिटीबैंक के अधिग्रहण की घोषणा करने वाले एक्सिस बैंक का शेयर 1.39 प्रतिशत मजबूत हुआ। कोटक सिन्क्योरिटीज लि. के इक्विटी शेयर (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, वैश्विक बाजारों में गिरावट के रूख का असर

निवेशकों पर पड़ा। कच्चे तेल के दाम में नरमी और रूस-यूक्रेन संकट खत्म होने की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में हाल की तेजी के बाद गिरावट रही। निवेशकों ने वायदा एवं विकल्प खंड में मासिक सौदों के निपटान के अंतिम दिन सतर्क रूख अपनाया। एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, जापान का निक्की और हांगकांग का हेंगसेंग नुकसान में, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहा।

यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में ज्यादातर में गिरावट का रूख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 5.09 प्रतिशत लुढ़ककर 107.68 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिका के अपने रणनीतिक भंडार से 18 करोड़ बैरल तेल जारी करने की रिपोर्ट के बाद कच्चे तेल के दाम नीचे आए। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थान निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,357.47 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे।

लघु बचत योजनाओं पर पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इन योजनाओं पर 2020-21 की पहली तिमाही से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पीपीएफ, एनएससी पर सालाना ब्याज दर पहली तिमाही में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, बिचिन्न लघु बचत योजनाओं के लिए 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इन योजनाओं पर वही ब्याज मिलेगा जो, चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021) में था। लघु बचत योजनाओं के लिए

● पीपीएफ पर मिलेगा 7.1 प्रतिशत ब्याज

ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है। एक साल की मियादी जमा पर ब्याज दर एक अप्रैल, 2022 से शुरू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.5 प्रतिशत होगी। वहीं बालिकाओं के लिए बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 प्रतिशत ब्याज प्रतिशत मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, पांच साल की वरिष्ठ नाररिक बचत योजना पर 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी। बचत खाते पर ब्याज पहले की तरह चार प्रतिशत होगा। एक साल से पांच साल की अवधि के लिए मियादी जमा पर ब्याज 5.5 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत होगा। जबकि पांच साल की आवती जमा (आरडी) पर 5.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

अशोक बिल्डकॉन को एनएचआई की राजगर्मा पहियोजना के लिए आशय-पत्र मिला: नई दिल्ली। अवसंरचना क्षेत्र की कंपनी अशोक बिल्डकॉन ने बृहस्पतिवार को यह कि उसे भारतीय राष्ट्रीय राजगर्मा प्राधिकरण (एनएचआई) से राष्ट्रीय राजगर्मा 150 सी के एक हिस्से के सड़कियां शामिल मौंडल (एवाएन) केतहत विकास के लिए आशय-पत्र मिला है।

सार्वजनिक सूचना
अपन जन्मा को एवाएन सूचित किता जात है कि की विशेषताएं पुर की परवतन पुरा गोपना में नम वरनी उत्तरा, जिसे नई म्हायत नगर, नई दिल्ली के नाम से जाना जात है, में स्थित मानव संख्या ओ-12-ए का भूतल, कुल्ल नगर हन में से एरिया परिषद 50 ग्राम पंच, राजगर्मा लागू 'वैधिक निर्माण 23.09.2021 के मानक' से मेलिंक है सभी गतिविधि को एवाएन सूचित किता जात है कि की कोरन पुरा और की अरवाला एवाएन पुरा इन सारी को भी विशेष बंधन पुर भी परवतन क्मा बंधन से एक राजगर्मा किता दिवस के मंगला से खरिद रहे हैं। और एसी के लिए, अच सेने को लिए सुवर्न डीवाला एवाएन क्मा सिमिटेड से सम्बन्ध किता है यह किने काली को उरता करती ने नोई एनए/रिज/ओरिगनर है का किता में न्हात का किता है तो क्मा अवसंरका में नो किता जात है तो पर सिमिटेड से वेकेशन में एर सेने के भीतर सूचित की है।
श्रीमती प्रमनू लती, अवसंरका, एएसी एएसोसिएट्स (ली) क्मा
खुनिट नंबर 7, बेसमेट, खौल नगर सी 78,
मैकूर, नरमती राय, If anybody,
person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property or objection to its mortgage, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims on the same have been waived off. No claim shall be entertained thereafter and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging the said property.
Vishal Chopra, Advocate
NARANG & Associates
D-28, Jangpura Extension,
New Delhi-110014.

PUBLIC NOTICE
My client, Home Plus Finance Pvt. Ltd., D-28/29, Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi is in the process of advancing a loan to Mrs. Rita Devi & Mr. Sukhdev Ray, against mortgage of Property No. J-22, (25 sq. yds.), part of Kharsa No. 142 & 143, Village Gonda Gujran Khadar, Block-J, Call No. 2, Karan Nagar, Shekhpura, Delhi. Mrs. Rita Devi has represented that she is the sole owner in possession of the said property on the basis of General Power of Attorney, Agreement to Sell & Will dated 03.02.2021 Having purchased the same from Mr. Ashok Tripathi and she is executing the Sale Deed of same property in favor of her husband Mr. Sukhdev Ray. If anybody, person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property or objection to its mortgage, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims on the same have been waived off. No claim shall be entertained thereafter and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging the said property.
Vishal Chopra, Advocate
NARANG & Associates
D-28, Jangpura Extension,
New Delhi-110014.

सार्वजनिक सूचना

श्रेट मोएडा ओघोमिग विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत M/s Rajhans Infratech Pvt.Ltd. के भूखण्ड संख्या-GH-068 सेक्टर-01 श्रेट मोएडा पर दिनांक 29.08.2018 को पुनर्दीक्षित मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदनुसार बिन्दु द्वारा पुन पुनर्दीक्षित मानचित्र स्वीकृति (Revised Sanction) हेतु दिनांक 29.11.2021 को ऑन-लाइन के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका आवेदन संख्या - SCR-12312 है। जिसमें पूर्व स्वीकृत भूवल सामग्री के डिजाईन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवेदियों द्वारा अपनी consent दी गई है या नहीं के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट ओवर अपनी आपति दर्ज करता सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिन्दु द्वारा प्रस्तुत गैरसहमत declarations एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यावेदन में सुबह 9:30 से साय 6.00 बजे के मध्य नियोजन विभाग के displayed में नजरो में किया जा सकता है। मानचित्रो ने 30प्रो अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट स्तामियो / संस को नोटीस जारी करने के 30 दिन के अन्दर आपतियां आमंत्रित की जाती है।
अतः उपरोक्त के निहदार्थ अपनी आपतियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यावेदन में श्रेट मोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या- 1 नॉलेज पार्क- 04, श्रेट मोएडा में स्थित वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु) विभाग में जिधिादित अवधि अवधि सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।
महाबन्धक (नियो)0/वास्तु0
श्रेट मोएडा प्राधिकरण

अब यूपी को चाहिए सबसे ज्यादा बिजली

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान से बढ़ सकती है प्रदेश सरकार की चुनौती

लखनऊ। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को लामबंदी के बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नए वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में अमृतक के सर्वाधिक 1,59,000 मिलियन (एक मिलियन बराबर 10 लाख) यूनिट से ज्यादा बिजली की आवश्यकता का अभूतपूर्व आकलन पेश किया है। इसके अनुरूप आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को अनेक मोर्चों पर बहुत कुशल प्रबंधन करना होगा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की आवश्यकता का आकलन किया है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहाँ बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आकलन के अनुसार महाराष्ट्र में जहाँ नए विद्युत वर्ष में 2,00,288 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत होगी, वहीं, उत्तर प्रदेश में 1,59,412 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश



कुमार वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आकलन है। वर्तमान में राज्य में एक साल में लगभग 1,15,000 से लेकर 1,20,000 मिलियन यूनिट तक बिजली की जरूरत पड़ती है। ऐसे में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 1,59,412 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता का आकलन चौकाने वाला है। हालांकि, इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बढ़ती गर्मी में अप्रैल-मई के बजाय मार्च से ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनिंग चलाए जाने से बिजली की खपत बहुत तेजी से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व खपत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कई मोर्चा पर बहुत कुशल प्रबंधन करना होगा। खासतौर पर तब, जब निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी आ-पक की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ

पछले 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की थी और उनके इस संघर्ष के अभी और तेज होने के आसार हैं। मार्ग में बताया कि सरकार को इस अनुमानित वॉर्ग की पूर्ति करने के लिए अपने सभी बिजली खरीद समझौतों की तत्काल समीक्षा करनी होगी और जिनसे बिजली नहीं खरीदी जा रही है, उन्हें भी इस खरीद के लिए तैयार रखा जाए। विद्युत संयंत्रों का बेहतर रखरखाव हो ताकि बीच में बिजली आपूर्ति बंद न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले तथा पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके अलावा फीड बैकलैसिंग करनी होगी और स्टोर में पर्याप्त सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि जो अकाल सामने आया है उसके मद्देनजर सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन और डिक्मा के अभियंता और अन्य अफसरों को अभी से कमर कस लेनी चाहिए और पूरी ईमानदारी से उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति के लिए युद्धस्थर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में कोई मुश्किल ना उठानी पड़े।

सड़क हादसे में
सास के बाद बहू
ने भी तोड़ा दम

नहेहपुर। सदर कोतावाली क्षेत्र के नउवाबाग धर्मकाँठ के समीप टुकू की चउपे में आ जाने से जहाँ 60 वर्षीय के माहिला की मौत हो गई थी। वही उसकी बहु गँधी रूप से घायल हो गई थी। जिसे उपचार के लिये कानपुर भेजा गया। जहाँ इलाज के दौरान भोर पहन उसने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बन्दकी कोतावाली क्षेत्र के दिलावरनपुर गांव निवासी 520 फ़ीरों लाल की पत्नी शिवकली पुत्र ननका के साथ बहु को लिवाने मायके में बसानवनपुर थाना हुसैनगढ़ गई थी। बढते हँ कि वापस लौटते समय बाइक जैसे ही शहर क्षेत्र के नउवाबाग धर्मकाँठ के समीप पहुँची वही पीछे से तेज रफ़्तार आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया। जिससे शिवकली की घटना थल पर मौत हो गई थी। जबकि बहु पुत्र ननका पत्नी शिवराज गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिसे उपचार के लिये जिला चिकित्सालय लाया गया। जहाँ चिकित्सक ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुवे कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिये रेफर कर दिया। वही परिणाम घायल महिला को हेरेंट न हो जाकर कानपुर में प्राइवेट में नर्सिंग होम में भर्ती कराकर इलाज कर रहे थे। जहाँ ज़न्दकी और मौत के बीच संघर्ष करते करते भोर पहन उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर विच्छिदर हुब हजेज दिया।

उच्च न्यायालय ने दी आरोपियों को जमानत

भारत के खिलाफ नारेबाजी करने का मामला

भाषा । प्रयागराज



लुलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारे लगाने के आरोपी इनायत अल्लाफ खान और दो अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं को मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों की अजीब बुध्दि का मंजूर कर लेना उल्टेखनीय है कि भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय मैच के बाद भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारे लगाने के आरोप में इन लोगों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का भी आरोप है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, याचिकाकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह झूठे मामला वास्तव में विचारार्थों के बीच दुश्मनी का नतीजा है और याचिकाकर्ताओं ने भारत के खिलाफ नारे लगाए हैं। पाकिस्तान के पक्ष में नारे नहीं लगाए, ए जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं लाये जाते जो कि भारतीय मूल्यों का बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि एन सीआरपी विद्यार्थी हैं जिन्का उज्ज्वल भविष्य है, मुकदमे की कार्यवाही में जब्तु धोमी गति से चल रही है और

इसका निर्यात जल्द आने की संभावना नहीं है। वकील ने कहा कि मुकदमे में अनुचित दुरी से याचिकाकर्ता अनिश्चितकाल के लिए जेल में रह सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलीली दी कि इन याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे भागेंगे नहीं और जांच में सहयोग करेंगे। वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को किसी तरह से प्रभावित करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत की अर्जी मंजू कर दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आगरा के जगदीशपुर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 505 (1) (बी) 124ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रधानाचार्य के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज

मुजफ्फरनगर। शाली जिले के कैरना कस्बे में नौवीं कक्षा की छात्रा को आत्महत्या के लिए उसमाने के आरोप में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार द्वारा खुया को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवा देने के बाद पुलिस ने अंकित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लड़की के परिवार ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अंकित स्कूल को प्रताड़ित कर रहा था और 26 मार्च को छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की इमारत से छांटों लगा दी लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन ने उन पर अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया था। स्थानीय लोगों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने बताया कि अंकित के खिलाफ प्राथमिकी की गई है और घटनास्थल से एक मुसाइड नोट भी बरामद किया गया है।

बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर

डीएम ने प्रश्नपत्रों के बंडल किए चेक

मीरजापुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित इंटरमीडिएट व हाईस्कूल के बोर्ड परीक्षाओं को नवेलविहीन व शुचितापूर्ण ढंग से सम्भ्र कराने के दृष्टिगत शासन के निर्देश के क्रम में आज जिलाशिक्षाधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्मरार व उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ विविध परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचकर परीक्षा केन्द्रों के डबल लाक में रखे गये प्रश्नपत्रों के सील बंदलो का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले अर कन्या इण्टर कालेज में पहुँचकर डबल लाक को खुलवाकर प्रश्नपत्र के बंदलो को चेक किया गया। तदुपरत निरीक्षण के क्रम में जिलाशिक्षाकारी द्वारा माता प्रसाद माता भीख इण्टर कालेज, स्मॉल नान्यवर काशीराम राजकीय बालिका इण्टर कालेज मुसफंगंज तथा रायस्थान इण्टर कालेज में पहुँचकर डबल लाक को खुलवाकर इंटरमीडिएट व हाईस्कूल के प्रश्नपत्र के बंदलो का विधिवत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में प्रश्नपत्रों के बंदल सील व बन्द पाये गये। निरीक्षणोपरान्त जिलाशिक्षाकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः निरीक्षण समाने प्रश्नपत्र के बंदलो को डबल लाक के अन्दरवाही में रखवाकर सील कराय गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र के कंट्रोल रूम में परीक्षा कक्षों में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरा के फुटेज को भी देखा गया। उन्होंने कहा कि सभी कक्ष के सी0सी0टी0वी0 कैमरा पूर्णतया संचालित रहें। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर गडबडी न पाये जाने पर कडी से कडी कार्यवाही की जायेगी।

डंपर की टक्कर से चार लोगों की मौत

बाराबंकी। जिले के लोनीकटड़ा थाना क्षेत्र के पूर्वार्चल एक्सप्रेस-वे पर हाथी का पुरवा गांव के पास एक कार और मिट्टी से लदे डंपर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बुधवार रात हुई जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही

मौत हो गई जबकि चौथे व्यक्ति ने लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। कार में सवार सभी लोग घटनास्थल पर ही मौत पाएँ। लखनऊ जिले के रहने वाले थे और लखनऊ जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक विविधनाथ यादव ने बताया कि तेज रफ़्तार से कार गांव के पास डंपर से टकराकर पल्टी पुलिस ने कार सवार सभी लोगों को पल्टुंकी पुलिस ने कार सवार सभी लोगों को बाहर निकालकर हैडरार्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां फिजिट्सको ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस

ने बताया कि चौथे व्यक्ति को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान इरशाद खान (30), अबुबकर राइन (32), लुकमान राइन (33) और इमरान (25) के रूप में हुई है।

तो गुटों के बीच झड़प में एक व्यक्ति को मौत: संभल। संभल में दो गुटों के बीच झड़प में एक व्यक्ति को मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार देर रात संभल कोतवाली के चौधरी सयम में दो गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें सरवर (35) नामक व्यक्ति घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक को

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन

पेट्रोल-डिजल और सैरों में कम दाम की बढ़ती कोमलों के विरोध में महानगर कांग्रेस कैबिनेट ने राष्ट्रीय आन्दोलन के अंतर्गत गृहवार को कुमार टॉकीज के निकट प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय जनता ने बढ़ती कोमलों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अनाम रोष व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा चार राज्यों में बीजेपी सरकार का रिटर्न गिफ्ट, एलपीजी पर 50 रुपये, पेट्रोल-डिजल पर रोजाना 80 रुपये की बढ़ोतरी के साथ जनता को दिया जा रहा है, आखिर जनता को किस बात की सजा दी जा रही है लगातार बड़े दाम इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार जनता के साथ दोहरा मार्पेट अपना रही है। बता दें कि पेट्रोल और डिजल की कोमलों में लगातार दूसरे दिन बुधवार को 80 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अभिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कोमल अब 97.01 रुपये प्रति लीटर होगी।



आगरा में कड़ाके की गर्मी के बीच कुछ इस अंदाज में ताज का दीदार करते पर्यटक

शिक्षा के साथ संस्कार होना जरूरी: शांतनु

बिंदकी (पतेहपुर)। शिक्षा के साथ संस्कार होना जरूरी है बिना संस्कार की शिक्षा अधूरी है। यह बात नगर के लंका रोड स्थित सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान इंटर कॉलेज में आयोजित प्रथम अलंकरण तथा वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध कथा वाचक शान्तनु जी महाराज ने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को शिक्षा के साथ संस्कार प्रणण अवश्य करना चाहिए। संस्कार से विनम्रता आती है। उन्होंने कहा कि सम्प्रदायों से डरें नहीं लक्ष्य की ओर आगे बढ़े सम्प्रदाता अवश्य मिलेगा। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री तथा जहानाबाद क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा से ही जीवन में उजाला आता है। विशिष्ट अतिथि बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने कहा कि शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व का विकास होने से ही जीवन में सम्प्रदाता मिलती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों ने मेंधाविचन को परीक्षा पन्त के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

७९ तथा कक्षा ११ के जिन छात्र-छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इसमें अंशिका पटेल, निष्ठा मिश्रा, शौर्य ओमप, यज्ञ प्रताप, ज्योत्सना देवी, कार्तिकेय शुक्ला, विधे पटेल आदि प्रमुख रहे। इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉ० श्रीकांत मिश्रा, प्रधानाचार्य अंबक कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शुक्ला, अध्यक्ष अशोक मिश्रा, अनुराग शुक्ला, आशीष तिवारी, अमित दिक्षित, अंकित मिश्रा, देवेंद्र सिंह, प्रशांत किशोर, रवि गुप्ता, अधिवक्ता सुनील तिवारी, विभव सिंह, तुराराम कांत शर्मा, विपुल पटेल, बबलू शर्मा, लक्ष्मीकांत, आशुतोष, अतुल द्विवेदी, विभोवर द्विवेदी, पुरुषोत्तम गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार नगर के लालौली रोड स्थित एमडी इंटरनेशनल स्कूल में भी रिजल्ट एंड प्राइस डिस्टिन्ग्विशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं को रिजल्ट के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जहाँ पर नन्हे-मुन्ने ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियाँ बटोरी। इस मौके पर प्रबंधक संदीप गुप्ता प्रधानाचार्य एसके पांडे आदि मौजूद रहे। अथ नगर के पैतबपुर मोहल्ले में कार्यलय इंटरनेशनल स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मेधावी बच्चों को ट्राफी और मेडल देकर किया सम्मानित

जहदपुर। सेंट जेवियर हाईस्कूल में कक्षा 03 से कक्षा 09 तथा 11 के बच्चों का रिपेट कांड विवरित कर मेधावी बच्चों को ट्रापी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों व उनके अभिभावकों में भी खुशी को लहर दौड़ा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ० कमनापति ठाकुर द्वारा दीर्घ प्रवृत्तित करके किया गया तथा मां सर्वस्वोत्तराय की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात् प्रधानाचार्य ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र बताया। प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को एकेडेमिक परफॉर्मेंस, मोस्ट प्रोमिषिंग एट लीडशिप, वेल् एंड वेल् डिसिप्लिन आदि अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वैशाली श्रीवास्तव, नीतू मालिनी त्रिपाठी ने किया। प्रबंधक नीतीश कुमार ने सभी अभिभावकों को धन्यवाद देते हुये अभिग व्यक्त किया, इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर पीपी पांडेय, अंजलि, जरीब अनवर, मनोरंजन प्रसाद, राजकुमार, आशीष अग्निहोत्री, जगन्नाथ, विजय श्रीवास्तव, विजय चंद्र पाठ आदि उपस्थित रहे।

जहां नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मुन्ना लाल सोनकर द्वारा मेधावियों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

प्रावि शिवराजपुर द्वितीय में पुरातन छत्र-छात्रों को किया गया सम्मानितः फतेहपुर। प्राथमिक विद्यालय शिवराजपुर द्वितीय में ग्राम प्रधान वंदना की अध्यक्षता में पुरातन छत्र अभिभावक एवं पुरातन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना गीत प्रस्तुत किया तथाछत्र पुरातन शिक्षकों का रोली टीका लगाकर और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुरातन छात्रों को रोली टीका एवं उपहार वितरित किए गए। कक्षा 01

से 05 तक के बच्चों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर पुरस्कर्तु किया गया। कक्षा 05 के छात्रों का विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर एसएमसी सदस्य संध्या देवी, नीलम देवी, रूचि देवी, ज्योति देवी आदि का भी सहभाग्य रहा। गांव से रिटायर हुए करीब आधा दर्जन शिक्षकों ने शिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रधानाधिका लीना साहू ने श्रुति, कीर्ति, नीरजा, संगीता, संध्या सहित सभी रसोइया आदि को भी धन्यवाद दिया।

एनएच ईग्लिश मीडियम में वितरित किये गये प्रगति पत्रः फतेहपुर। एनएच ईग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रगति पत्र वितरण का कार्यक्रम

आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि समाजसेवी अशोक तपस्वी, मौजूद रहे। छात्रों ने तिलक लगाकर व प्रबंधक मीलाना मो 03मर शर्मा प्रधानाचार्य प्रतीक शुक्ल ने पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण कर अतिथियों अभिभावकों का स्वागत किया। अशोक तपस्वी व उक्तृष्ट परदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को शिल्प, प्रसारित-पत्र और मेडेड दिए गए। मुख्य अतिथि ने बच्चों को शिक्षा और अनुशासन के संयुक्त होने पर अच्छे परिणाम आने के बारे में बताया और सभी को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने पर जोर दिया। प्रधानाचार्य ने शिक्षा की गुणवत्ता और आवश्यकता पर जोर दिया और विद्यार्थी खेल शिक्षा और कंप्यूटर कोडिंग शिक्षा को शुरुआत होने की जानकारी दी।

तीन तलाक़ विरोधी कार्यकर्ता निंदा के भाजपा छोड़ने की धमकी, छह लोगों पर मामला दर्ज

खलनाथ पुलिस ने तीन बल्लाक-भारी कारकात नंदा खान को बाराथी जन्ता पार्टी (भाषा) छोड़ने की धमकी देने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खान को भाषा नहीं छोड़ने पर खान से मारने की धमकी दी गई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें खान के पति शरीर रज्जा खान और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। रज्जा खान ने नंदा को फौरन तौर पर तीन बर तलाक बोलकर तलाक दिया था। नंदा ने पीटीआर भाषा को बताया, मैं 26 मार्च को एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहाँ मैं सरसुराल वालों और कुछ रिश्तेदारों ने मुझे भाषा छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा न करने पर मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। स्नातकोत्तर तन शिक्षा प्राप्त नंदा खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाषा में शामिल हुई और पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सदस्य भी हैं। अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फेलू दिसा और देहेज की शिकायत दर्ज करने के बाद नंदा सुरियायों में आई थी।

भाजपा का समर्थन करने
पर मुस्लिम युवक को
मिली धमकी, प्राथमिकी

बदलायूँ। उत्तर प्रदेश के बदलायूँ जिले में एक मुस्लिम युवक को कथित तौर पर भाजपा का समर्थन करने पर उसके गांव के लोगों से ही जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहत्संविताव को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवक ने इस संबंध में बिसौली कोतवाला थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि कोतवाला बिसौली की अंतर्गत आने वाले गांव लक्ष्मीपुर के निवासी शाहस्वर सैफ़ी ने आरोप लगाया कि है काल में वो एक विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के बाद से उसे ग्रामीणों से धमकी मिल रही है। युवक को मुताबिक पैसेबुक पर भी उसके खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि बुधवार को हमें शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि मामले में ग्रामीणों की दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है।

बुलंदशहर में पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की

बुलंदशहर। बुलंदशहर में तैनात एक पुलिस हेड कंस्टेबल ने बृहस्पति रात को अपनी सुखादी बंदूक से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मुताक है कि कंस्टेबल ब्रजवीर सिंह बुलंदशहर के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक (नगर) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया, हेड कंस्टेबल ब्रजवीर सिंह (56) रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर गाई के पद पर तैनात थे। उनका घर पुलिस लाइन के नजदीक है। दोपहर में सिंह अपनी सरकारी बंदूक पर धावा गा.जहाँ उन्होंने खुद को गोली मारी (ली)। घटना के बाद पास के थाने से पुलिस की टीम घब्र पहुँची। तिवारी ने बताया, 'घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

